



सुरक्षित

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या 3822 वर्ष 2022

तेजवीर...

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता: श्री हेमंत शर्मा, श्री ओमवीर सिंह राजपूत, श्री सौरभ कुमार
प्रतिपक्षियों के लिए अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

एवं एक अन्य सम्बद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

(माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर द्वारा प्रदत्त)

1. इस निर्णय से, हम प्रस्तुत आपराधिक अपील और संबंधित आपराधिक अपील संख्या 5320 वर्ष 2021 पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं, जो दोनों सुश्री दीपिका तिवारी, तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-1, बुलंदशहर दिनांक 25.10.2021 के सत्र परीक्षण संख्या 644 वर्ष 2019, राज्य बनाम राज्य बनाम तेजवीर और अन्य के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होते हैं। उक्त निर्णय और आदेश द्वारा, विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में, 'भ०द०वि०') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोनों अपीलों में दोषी ठहराया है और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर, चूक में अपीलकर्ता को दो साल की अवधि के लिए और कठोर कारावास काटने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, सभी अपीलकर्ताओं को भ०द०वि० की धारा 304-बी, 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 (संक्षेप में, 'डीपी अधिनियम') के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह दोषसिद्धि और सजा है जिसे प्रत्येक अपीलकर्ता प्रस्तुत अपील में चुनौती देता है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. चोखेलेल पुत्र कमल सिंह, निवासी चौगनपुर, थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2019 को शाम 5:45 बजे थाना रामघाट, जिला बुलंदशहर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ('संक्षेप में 'प्राथमिकी') दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी दो बेटियों ममता और चंद्रावती की शादी दो भाइयों तेजवीर और राकेश से की थी, जो दोनों नानकराम के बेटे थे। गांव गंगागढ़, थाना रामघाट, जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। उन्होंने अपनी लिखित प्रथम सूचना में बताया कि आज यानी 30.07.2019 को उनकी छोटी बेटी चंद्रावती ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बहन ममता को दहेज की मांग और उसकी बहन के बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण नानकराम के पुत्र तेजवीर, नानकराम की पत्नी रामा, नानकराम की पत्नी मुन्नी और किशोरी लाल के पुत्र नानकराम ने जहर दिया है। चोखेलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही परिवार के सभी सदस्य कार से गंगागढ़ पहुंचे, लेकिन तब तक जहर शरीर को अपने ऊपर ले चुका था। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि सूचनाकर्ता की बेटी ममता ने उसे बताया कि उसकी सास, ससुर, पति और भाभी (नानाद) ने उसे जबरन जहर पिलाया था। सूचनाकर्ता ने कहा कि वे ममता को चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, जब अतरौली में रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्राथमिकी में इस मामले में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि ममता का शव थाना रामघाट के सामने खड़े वाहन में सूचनाकर्ता के पास था।

3. उक्त मामले के आधार पर अपराध संख्या 106 वर्ष 2019 में धारा 498-ए, 304-बी भ०द०वि० और डीपी एक्ट की धारा 3/4 के तहत तीन अपीलकर्ताओं के अलावा नानकराम की बेटी रमा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

4. 30.07.2019 को थाना रामघाट, जिला बुलंदशहर के सब-इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह और पंच गवाहों की उपस्थिति में मनोज कुमार सिंह, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिबई, जिला बुलंदशहर द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की गई। इसके बाद मृतक का शव परीक्षण किया गया, जो 31.07.2019 को किया गया। निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटें देखी गईं:

"(1) पंचर घाव का आकार 0.3x0.3 सेमी दाईं ओर उपरोक्त क्लैविकुलर क्षेत्र में मध्य हंसली क्षेत्र मौजूद है।



(2) पंचर का आकार दाईं ओर गर्दन पर 03x03 सेमी, दाएं औसत दर्जे से 3 सेमी ऊपर, और हंसली की हड्डी से होगा।

(3) दाहिने कलाई के जोड़ के ठीक नीचे हाथ के पृष्ठीय भाग पर मौजूद लिकोप्लास्ट टेप के साथ कपास झाड़ू।

(4) बछड़े की मांसपेशियों पर दाहिने निचले अंग पर मौजूद लिकोप्लास्ट टेप के साथ कपास झाड़ू।

(5) चोट संख्या (1) और (2) अन्वेषण पर उप-शिरा क्रमशः पंचर पाया गया और आंतरिक जुगलर नस को पंचर पाया गया।

5. शव परीक्षण चिकित्सक ने टिप्पणी की कि कोई राय नहीं दी जा सकती है (मृत्यु के कारण के रूप में) और विसरा को रासायनिक और फॉरेंसिक जांच के लिए संरक्षित किया गया था। डॉक्टर की राय में, मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए, विसरा को रासायनिक, विष विज्ञान और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए संरक्षित किया गया था।

6. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गाजियाबाद की दिनांक 08.08.2019 की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि पांच भागों में प्राप्त विसरा में ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक की उपस्थिति दिखाई देती है।

7. अपराध की जांच करने वाले सर्किल ऑफिसर, देबई, बुलंदशहर ने तीन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन मृतक की भाभी रमा को दोषमुक्त कर दिया, यह देखते हुए कि यह उसके लिए झूठे फंसाए जाने का मामला है।

8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने 02.12.2019 को संज्ञान लिया और आरोपी को तलब किया। वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'द०प्र०स०') की धारा 207 के तहत संबंधित अभियोजन पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत कीं। इसके बाद, बुलंदशहर के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सुमित प्रेमी द्वारा 02.12.2019 को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

9. सुश्री श्वेता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-1, बुलंदशहर द्वारा दिनांक 06.01.2020 के आदेश के तहत चार आरोप तय किए गए थे। अपीलकर्ताओं पर पहली गिनती में भ०द०वि० की



धारा 498-ए, दूसरी गिनती में भ०द०वि० की धारा 304-बी और तीसरी और चौथी गिनती में डीपी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए थे। धारा 302 भ०द०वि०/34 के तहत एक वैकल्पिक आरोप तय किया गया था। अपीलकर्ताओं ने खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमे का दावा किया। अपीलकर्ताओं ने सुश्री दीपिका तिवारी के समक्ष अपना मुकदमा खड़ा किया, जिन्होंने इस मामले में सभी सबूतों को सुना। परीक्षण 21.10.2020 को शुरू हुआ।

10. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों की जांच की है:

- (1) अ०सा०-1, चोखेलाल, सूचनाकर्ता और मृतक का पिता;
- (2) अ०सा०-2, चंद्रावती, तथ्य का एक अन्य गवाह और मृतक की बहन;
- (3) अ०सा०-3, ओमवती, मृतक की मां;
- (4) अ०सा०-4, बंटी सिंह, मृतक का भाई;
- (5) अ०सा०-5, डॉ. अजय कुमार, ने शव परीक्षण किया;
- (6) अ०सा०-6, लेडी कांस्टेबल रितु ने चेक प्राथमिकी दर्ज कराई; तथा,
- (7) मामले के विवेचनाधिकारी सीओ विक्रम सिंह, जिन्होंने एक साइट-प्लान तैयार किया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

11. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया है:

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	संक्षिप्त विवरण के साथ दस्तावेज प्रदर्शित करें
1	प्रदर्श क-1	लिखित रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 को थाना रामघाट, जिला बुलंदशहर में दर्ज की गई और अ०सा०-1, चोखेलाल द्वारा साबित की गई
2	प्रदर्श क-2	मृतक ममता की शव परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31.07.2019, अ०सा०-5, डॉ. अजय कुमार द्वारा साबित की गई
3	प्रदर्श क-3	दिनांक 30.07.2019 की प्राथमिकी की जांच करें, अ०सा०-6, लेडी कांस्टेबल रितु द्वारा साबित किया गया
4	प्रदर्श क-4	अपराध संख्या 106 वर्ष 2019 से संबंधित रोज़नामचा प्रविष्टि संख्या 30, समय 17.45, दिनांक 30.07.2019 की कार्बन कॉपी, अ०सा०-6, महिला कांस्टेबल रितु द्वारा साबित की गई
5	प्रदर्श क-5	घटनास्थल की साइट प्लान दिनांक 02.08.2019, अ०सा०-7, सीओ विक्रम सिंह द्वारा सिद्ध किया गया
6	प्रदर्श क-6	अ०सा०-7, सीओ विक्रम सिंह द्वारा साबित की गई चार्जशीट
7	प्रदर्श क-7	पंचायतनामा (जांच रिपोर्ट) दिनांक 30.07.2019

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8	प्रदर्श क-8	शव का चालान नैश
9	प्रदर्श क-9	फोटो लाश
10	प्रदर्श क-10	सीएमओ को पत्र
11	प्रदर्श क-11	नमूना मुहर
12	प्रदर्श क-12	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनांक 26.09.2019

12. विचारण न्यायाधीश ने दिनांक 25.10.2021 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया था।

13. आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, आपराधिक अपील संख्या 3822 वर्ष 2022 को अपीलकर्ता, तेजवीर द्वारा दायर किया गया है, जबकि आपराधिक अपील संख्या 5320 वर्ष 2021 अपीलकर्ताओं, नानकराम और मुन्नी द्वारा दायर किया गया है।

14. हमने आपराधिक अपील संख्या 3822 वर्ष 2022 को प्रमुख अपील के रूप में सुना है क्योंकि दोनों अपीलें विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं और एक ही अपराध से भी संबंधित होती हैं।

15. दोनों अपीलों के समर्थन में अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार राय, श्री हेमंत शर्मा और श्री ओमवीर सिंह राजपूत और राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल अस्थाना को सुना।

16. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर, हम पाते हैं कि इस बात में कोई दलील नहीं है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भ०द०वि० की धारा 304-बी, 498-ए और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन उन्हें धारा 302 भ०द०वि०/34 के तहत वैकल्पिक आरोप में दोषी ठहराया है और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई है। यह दोषसिद्धि और सजा है, जिस पर अपीलकर्ता हमारे सामने हमला करते हैं।

17. धारा 302 भ०द०वि०/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि एक होने के कारण, यह अभियोजन पक्ष है, जिसे उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करना है।

18. यह एक ऐसा मामला है, जहां स्पष्ट रूप से, तथ्य के सभी चार अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए हैं और पुलिस के सामने, अपराध दर्ज करने के समय, और बाद में पुलिस के सामने दिए गए बयानों में, जांच के दौरान अपने बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इस

मामले की दो विशेषताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए; एक सामान्य, और, दूसरा, इतना सामान्य नहीं है, यदि दुर्लभ नहीं है। इस मामले में अक्सर होने वाली विशेषता या चुनौती यह है कि मृतक की मृत्यु उसके वैवाहिक घर के दायरे में हुई थी, जहां अपीलकर्ता सभी मामलों के नियंत्रण में थे। यह आम बात है क्योंकि किसी भी भारतीय घर में, देश के कुछ स्थानों को छोड़कर, यह पत्नी है, जो शादी के बाद, अपना घर छोड़ देती है और अपने पति या / और ससुराल वालों के साथ अपने घर में बस जाती है। इसलिए, यदि एक अप्राकृतिक मृत्यु या हिंसा से मृत्यु पत्नी का उसके वैवाहिक घर में भाग्य है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा पत्नी की मृत्यु के बारे में बुनियादी तथ्यों को स्थापित करने के बाद, जो अप्राकृतिक है या अपराध का परिणाम है, तो मृतक के पति और उसके रिश्तेदारों के कंधों पर बोझ पड़ता है, जिनके साथ वह रहती थी, यह समझाने के लिए कि अप्राकृतिक मृत्यु कैसे हुई।

19. इस मामले की असामान्य विशेषता यह है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में, एक पत्नी, जो अपने वैवाहिक घर में अप्राकृतिक मृत्यु के कारण मर जाती है, उसके पास अपनी कहानी बताने के लिए कोई गवाह नहीं है, स्पष्ट कारण यह है कि उसके पति और ससुराल वाले, एक साथ बंधे हुए हैं, सामान्य हित के धागे के साथ, अपने स्वयं के रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएंगे और उन्हें एक जघन्य अपराध के लिए दंडित होने के परिणामों के लिए उजागर करेंगे; लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहाँ, असामान्य विशेषता, जिसके बारे में हमने बात की है, वह यह है कि अपने वैवाहिक घर की सीमा में, मृतक की एक बहन थी जो उसके साथ होने वाली हर चीज की चश्मदीद गवाह थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बहनों की शादी पूरे खून के दो भाइयों से हुई थी। इस गवाह की गवाही, जो निस्संदेह एक चश्मदीद गवाह है, बहुत महत्व रखती, अगर वह आदर्शवाद के मार्ग पर चलती, स्पष्ट और सच्चाई से बोलती। लेकिन, ऐसा लगता है कि वह अपने ससुराल वालों को बचाने के बहुत ही सांसारिक विचार का शिकार नहीं हुई है, जो उसकी बहन के ससुराल भी हैं। उसकी शादी उसी घर में हुई है और अगर उसे दोषी ठहराया जाता है, तो जो लोग कानून की सजा भुगतेंगे, वे उसके पति के माता-पिता और परिजन होंगे। शायद यही विचार है, जिसने इस असामान्य चश्मदीद गवाह को अपने गोदी में कुछ झूठ और अन्य आधे सच बोलने पर मजबूर कर दिया है। बेशक, अन्य गवाहों की तरह, उसे भी अभियोजन पक्ष द्वारा मुकर दिया गया है और जिरह की गई है। यदि वास्तव में, मृतक



की बहन, अ०सा०-2, चंद्रावती सहित गवाहों ने झूठ और आधा सच बोला है, तो हम जल्द ही इस फैसले में जांच करेंगे।

20. अपराध की उत्पत्ति से पता चलता है कि सूचनाकर्ता और अ०सा०-1, चोखेलाल, मृतक के पिता, ने 30.07.2019 को अपनी छोटी बेटी, चंद्रावती से फोन पर सूचना प्राप्त की, इस आशय की कि उसकी बहन, ममता को उसके पति तेजवीर, भाभी रमा, सास मुन्नी और ससुर नानकराम ने दहेज की अपूर्ण मांग और बच्चे को जन्म देने में विफलता के कारण जहर दिया था। मृतक की मृत्यु के बाद दर्ज प्राथमिकी से पता चलता है कि उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर, सूचनाकर्ता परिवार के सभी सदस्यों के साथ, अपनी कार में मृतक के ससुराल में गया, केवल यह पता चला कि जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि उसकी बेटी ममता (बाद में मृतक) ने उसे बताया कि उसकी सास, ससुर, पति और भाभी (नानाद) ने उसे जहर खाने के लिए मजबूर किया था। उक्त तथ्य को जानने पर, सूचनाकर्ता ने अपनी बेटी के साथ चिकित्सा सहायता लेने के लिए अस्पताल जाना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे अतरौली पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद ही पहले सूचनाकर्ता ने पुलिस को अपराध की सूचना दी।

21. सूचनाकर्ता और मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों, जो यहां गवाह हैं, का यह रुख जांच के दौरान लगातार बना रहा।

22. अ०सा०-1, मृतक के पिता और पहला सूचनाकर्ता, कटघरे में मुकर गया और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। घटना के बारे में उन्होंने अपनी परीक्षा में कहा है कि 30.07.2019 को उन्हें अपनी छोटी बेटी चंद्रावती से सूचना मिली कि ममता की मृत्यु हो गई है। जब वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मृतक के ससुराल पहुंचा, तो ममता की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने प्राथमिकी अपने गांव के एक लड़के बंटी सिंह (जबकि वास्तव में बंटी सिंह उनके बेटे हैं) को लिखवाया और इसे थाना रामघाट में सौंप दिया। उन्होंने जो लिखित जानकारी लिखी थी, वह अभिलेखों पर है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने अपनी जांच में आगे कहा है कि उन्हें इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी ममता को उनके पति तेजवीर, सास मुन्नी और ससुर नानकराम ने जहर देकर मार डाला था। यह इस स्तर पर था कि गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए प्रार्थना की गई थी और उस प्रार्थना को स्वीकार करने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा उससे जिरह की गई थी।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी में, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे उसकी छोटी बेटी चंद्रावती का फोन आया था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि ममता को उसके पति, सास और ससुर द्वारा जहर दिया गया था, साथ ही उन मुद्दों को भी निर्दिष्ट किया गया था जिनके कारण उन्होंने यह बुरा काम किया। उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि जब वह परिवार के साथ ममता के घर पहुंचे तो जहर शरीर पर चढ़ गया था, लेकिन ममता ने उन्हें बताया कि उनकी सास, ससुर, पति और भाभी ने उन्हें जबरन जहर पिलाया था। वह तुरंत अपनी बेटी को अस्पताल ले गए, लेकिन जब वे अतरौली में थे तब ही उसकी मृत्यु हो गई।

24. अब, इस प्राथमिकी की विषय-वस्तु की पुष्टि की गई है और गवाह ने अपनी परीक्षा-इनचीफ में साबित किया है, लेकिन अपने कटघरे में घटना के बारे में विरोधाभासी बात की है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है कि अगर गवाह ने प्राथमिकी की सामग्री की पुष्टि की है, जहां यह कहा गया है कि ममता जीवित थी, जब वह उसके पास पहुंचा और उसे बताया कि उसे अपीलकर्ताओं द्वारा जहर पीने के लिए मजबूर किया गया था, तो यह गवाह अपने कटघरे में कैसे कह सकता है कि जब वह ममता के घर पहुंचा, वह पहले ही मर चुकी थी और उसे नहीं पता था कि अपीलकर्ताओं ने उसे जहर दिया था या नहीं। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने तथ्य की कुछ गलत धारणा के तहत या किसी प्रेरणा से गलत तथ्य सामने रखते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में प्राथमिकी का विशेष महत्व होता है। हालांकि, यह ठोस सबूत नहीं है, यह घटना का सबसे पहला विवरण है, और इसलिए, सबसे सच्चा माना जाता है, अलंकरण, बाद के विचार, डिजाइन या हेरफेर से मुक्त। यही कारण है कि, अगर इसे परिस्थितियों में शीघ्र नहीं दिखाया जाता है और एक अस्पष्टीकृत देरी के बाद दर्ज किया जाता है, तो संभावित पूर्व-ध्यान के साथ, प्राथमिकी को दिया गया वजन खो जाता है या बहुत कम हो जाता है।

25. इस संबंध में, जय प्रकाश सिंह बनाम सुप्रीम न्यायालय बिहार राज्य और अन्य, (2012) 4 एस.सी.सी. 379, जहां यह अवधारित किया गया है:

"12. एक आपराधिक मामले में प्राथमिकी सबूत का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है, हालांकि सबूत का ठोस टुकड़ा नहीं हो सकता है। किसी अपराध के कमीशन के संबंध में प्राथमिकी को तुरंत दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक अपराधियों के नाम और

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम भी हैं। यदि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब होता है, तो यह बड़ी संख्या में परामर्शों/विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप रंगीन संस्करण, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी पेश करने में सहजता का लाभ खो देता है। निस्संदेह, प्राथमिकी दर्ज करने में तत्परता सूचनाकर्ता के बयान की सच्चाई के बारे में एक आश्वासन है। तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी में इस बात का प्रत्यक्ष विवरण दर्शाया गया है कि वास्तव में क्या हुआ है, और प्रश्न में अपराध के लिए कौन जिम्मेदार था। (थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य [(1972) 3 एस.सी.सी. 393: 1972 एस.सी.सी. (सीआरआई) 543: ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 501], पंजाब राज्य बनाम सुरजा राम [1995 पूरक (3) एस.सी.सी. 419: 1995 एस.सी.सी. (सीआरआई) 937: ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 2413] , गिरीश यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1996) 8 एस.सी.सी. 186: 1996 एस.सी.सी. (सीआरआई) 552] और तकदिर शमसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य [(2011) 10 एस.सी.सी. 158 : (2012) 1 एस.सी.सी. (सीआरआई) 218: ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 37] "।

26. जाहिरा तौर पर, इस गवाह ने झूठ बोला है और अदालत से सच छुपाया है, जो फिर भी उसकी झूठी गवाही के सभी कवच के पीछे से झाँकता है। अपनी जिरह में, अ०सा०-1 ने कहा है:

"घटना के समय मेरी बेटी चन्द्रवती पत्नी राकेश भी अपनी ससुराल ग्राम गंगागढ़ में थी। मुलजिमान गंगागढ़ में एक ही मकान में रहते हैं और वही एक ही खाते पीते हैं। मैं घटना की बावत बोलता गया था और तहरीर बन्टी लिखता गया। तहरीर बन्टी सिंह ने लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनायी थी फिर मैंने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर किये थे। तहरीर मे बंटी सिंह ने वही लिखा था जो मैंने बोला था।

यह कहना गलत है कि जब हम लोग सूचना पर अपनी बेटी ममता की ससुराल पहुंचे तो उस समय तक ममता जीवित हो। यह भी कहना गलत है कि ममता ने मुझे व मेरे अन्य परिवारी जन को मेरी छोटी बेटी चन्द्रवती की मौजूदगी में यह बताया हो कि "मुझे मेरी सास, ससुर, पति व ननद ने जबरन जहर पिला दिया है।" यह कहना भी कहना गलत है कि हम उपचार के लिये ममता को अलीगढ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में अतरौली पर ममता ने दम तोड़ दिया हो और ममता की मृत्यु हो गयी हो।



यह कहना भी गलत है कि दिनांक 30.7.19 को मेरी पुत्री ममता को अतिरिक्त दहेज की मांग पूर्ण न होने के कारण मुलजिमान तेजवीर नानकराम, मुन्नी ने मिलकर एकराय मशवरा होकर ममता को जहर देकर मार दिया हो।

यह कहना भी गलत है कि मुलजिमान से मिलकर उन्हें बचाने के लिये आज मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ और सही बात को छिपा रहा हूँ।

मैंने आज से पहले कहीं पर भी किसी को भी या किसी पुलिस अधिकारी को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को यह नहीं बताया कि मेरी बेटी ममता की हत्या (जहर देकर) मुलजिमान तेजवीर, नानराम व मुन्नी देवी व रामा ने नहीं की। यह बात आज मैं पहली बार कह रहा हूँ।

यह बात सही है कि अब हमारा इस मुकदमे के मुलजिमान तेजवीर आदि से फैसला हो गया है।

यह कहना सही है कि मुलजिमान से फैसला हो जाने के कारण मुलजिमान के पक्ष में गवाही दे रहा हूँ।

यह बात सही है कि मृतका ममता के साथ घटना ससुराल में हुई थी और मृत्यु रास्ते में हुई थी।"

27. यदि हम इस गवाह की जिरह को देखें, तो इसके शुरुआती भाग में उसका रुख इस बात की पुष्टि करता है कि सूचनाकर्ता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के वहां पहुंचने पर ममता पहले ही मर चुकी थी और वह अतरौली में अलीगढ़ जाते समय रास्ते में नहीं मरी थी, जबकि उसे इलाज के लिए वहां ले जाया जा रहा था। उन्होंने अपनी जिरह के पहले हिस्से में इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि ममता ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उनकी सास, ससुर, पति और भाभी ने उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर किया था। हालांकि, अपनी जिरह के बाद के हिस्से में, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि जब घटना मृतक के ससुराल वालों के घर पर हुई थी, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। अपनी जिरह के शुरुआती हिस्से में, इस गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि प्राथमिकी बंटी सिंह द्वारा अपने आदेश पर अनायास लिखी गई थी और उस पर उसके हस्ताक्षर थे। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि लिखित जानकारी में केवल वही तथ्य हैं, जो उन्होंने बंटी सिंह को लिखे



थे। प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब सूचनाकर्ता ममता के घर पहुंचा, तो उसने उसे बताया कि उसकी सास, ससुर, पति और भाभी ने उसे जबरन जहर पिलाया था और वे उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही अटरौली में उसकी मौत हो गई।

28. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस गवाह ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने पहले किसी भी समय किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बताया था कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को जहर नहीं दिया था। जिरह में क्लिंकर का आंकड़ा है, जहां यह गवाह स्वीकार करता है कि उसने अपने कटघरे में साक्ष्य दोषमुक्ति के बारे में बात की थी, क्योंकि उसने अपीलकर्ताओं के साथ समझौता किया था।

29. यह कानून नहीं है कि एक अभियोजन पक्ष का गवाह, जो मुकर जाता है, अपने साक्ष्य को निरर्थक बनाता है। यहां तक कि अगर अभियोजन पक्ष का गवाह मुकर जाता है, या उस मामले के लिए, एक बचाव पक्ष का गवाह, तो वह अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अपने चरित्र को बरकरार रखता है। गवाह का चरित्र या अभिविन्यास कभी नहीं बदलता। इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही, जो मुकर जाती है, को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए या अभिलेखों से छूट नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि, इसके ऐसे प्रासंगिक हिस्सों के लिए अभी भी विचार किया जा सकता है, जो अभियोजन पक्ष का समर्थन करता है, या कुछ हद तक बचाव पक्ष भी हो सकता है। आखिरकार, एक मुकदमे का उद्देश्य, जहां गवाह गवाही देते हैं कि क्या वे वफादार रहते हैं या उस पक्ष के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं जिसके द्वारा उन्हें बुलाया जाता है, यह सब की सच्चाई का निर्धारण करना और जितना हो सके न्याय प्रदान करना है।

30. अदालत को जो कुछ भी करना है, एक ऐसे मामले में जहां गवाह मुकर गया है, अपने साक्ष्य को इस अर्थ में कुछ हद तक सावधानी के साथ देखना है कि उस पर कार्य करने से पहले, अन्य सबूतों से पुष्टि की मांग की जानी चाहिए। इस मुद्दे की उच्चतम न्यायालय द्वारा के.पी. पुलिस उपाधीक्षक, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 958 द्वारा राज्य, जहां यह अवधारित किया गया है:

"18. जब अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया कोई गवाह अभियोजन पक्ष के संस्करण के खिलाफ गवाही देता है और अपने स्वयं के पहले दर्ज किए गए बयानों के

खिलाफ जाता है, तो अभियोजन पक्ष न्यायालय से ऐसे गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित करने का अनुरोध कर सकता है और अपने स्वयं के गवाह से जिरह करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांग सकता है। यह एक परीक्षण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष के 51 गवाह हैं और यह भी एक तथ्य है कि उनमें से कई धारा 161 द०प्र०स० के तहत पुलिस के सामने और कुछ मामलों में द०प्र०स० की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले के बयानों के खिलाफ मुड़कर मुकर गए हैं। यह घटना नई नहीं है, वास्तव में दुख की बात है कि आज हमारी आपराधिक अदालतों में यह एक सामान्य घटना है, जो अभियोजन पक्ष की निराशा और हताशा के लिए बहुत अधिक है। इसलिए, यह मामला कोई अपवाद नहीं है। इसके बावजूद, हालांकि, प्रस्तुत मामले में गवाह हैं, विशेष रूप से अ०सा०-1, अ०सा०-2, अ०सा०-3, अ०सा०-15 और अ०सा०-49, जिनके साक्ष्य, न्यायालय के समक्ष उनकी गवाही के रूप में, प्रस्तुत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। यहां एक तथाकथित शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य मूल्य के बारे में एक शब्द।

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम') एक पक्ष को, न्यायालय की अनुमति से, अपने स्वयं के गवाह से जिरह करने की अनुमति देता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 मूल रूप से इस प्रकार है:

"154. पक्षकार द्वारा अपने स्वयं के गवाह से प्रश्न न्यायालय अपने विवेक से, उस व्यक्ति को अनुमति दे सकता है जो गवाह को बुलाता है कि वह उससे कोई भी प्रश्न पूछे, जिसे प्रतिकूल पक्ष द्वारा जिरह में रखा जा सकता है।

20. कलकत्ता उच्च न्यायालय, खिजीरुद्दीन सोनार बनाम सम्राट, 1925 एस.सी.सी. ऑनलाइन कल. 259 ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 की व्याख्या करते हुए कहा कि "जब अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाए गए एक गवाह को साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के प्रावधानों के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह करने की अनुमति दी जाती है, तो उस प्रविधि की अनुमति का परिणाम उस गवाह को पूरी तरह से बदनाम करना है, न कि केवल उसकी गवाही के एक हिस्से से छुटकारा पाने के लिए।



21. लेकिन खिजीरुद्दीन के मामले में इस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने प्रफुल्लकुमार सरकार बनाम प्रफुल्लकुमार सरकार के मामले में खारिज कर दिया। सम्मट, 1931 एस.सी.सी. ऑनलाइन कैल 7. उच्च न्यायालय इस विशिष्ट प्रश्न के संबंध में एक खंडपीठ के संदर्भ का उत्तर दे रहा था कि क्या एक गवाह की गवाही, जिसे उस पक्ष द्वारा जिरह की गई थी, जिसने उसे पेश किया था, को पूरी तरह से, आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए, या बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रैंकिन ने तीन अन्य न्यायाधीशों और स्वयं के लिए बोलते हुए, निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ का उत्तर दिया:

"24. मेरी राय में, तथ्य यह है कि एक गवाह साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत निपटाया जाता है, भले ही उस धारा के तहत उसे क्रेडिट के लिए "जिरह की जाए" जाती है, किसी भी तरह से जूरी को यह निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है कि वे कानून में उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं करने के लिए बाध्य हैं, या यह कि जिस पक्ष ने उसे बुलाया और जिरह की, वह उसके साक्ष्य के किसी भी हिस्से से कोई लाभ नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, कानून का कोई नियम नहीं है कि यदि कोई जूरी सोचती है कि एक गवाह को एक बिंदु पर बदनाम किया गया है, तो वे उसे दूसरे बिंदु पर श्रेय नहीं दे सकते हैं। कानून का शासन यह है कि यह जूरी को कहना है।

खंड पीठ द्वारा बताए गए सात प्रश्नों में से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें चार का उत्तर देना चाहिए, अर्थात्-

(3) क्या "शत्रुतापूर्ण" के रूप में माने जाने वाले गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए;

(4) क्या इसे अब तक अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह गवाह को बुलाने वाले पक्ष के पक्ष में है;

(5) क्या इसे अब तक अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह विरोधी पक्ष के पक्ष में है। इन तीन सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा।



(6) क्या अब तक का पूरा साक्ष्य दोनों पक्षों को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जूरी के पास जाना चाहिए कि इसका मूल्य क्या है।

25. इस प्रश्न के लिए, मैं "हां" का उत्तर देने में संतुष्ट रहूंगा,...."

22. न्यायमूर्ति बकलैंड, उपरोक्त मामले में, अपनी सहमति राय में मानता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि एक गवाह के साक्ष्य, जिसे उसके पक्ष द्वारा जिरह की गई है, को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। उनकी राय में, यह जूरी (या न्यायाधीश) के लिए है कि वह ऐसे गवाह की गवाही के मूल्य के बारे में एक राय बनाए।

23. बाद में इस न्यायालय ने जागीर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली), (1975) 3 एस.सी.सी. 562 में तत्स्य विपरीत माना और खिजीरुद्दीन में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी दे दी। जस्टिस भगवती ने जागीर सिंह में यह कहा था:

"7. अब, उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पूरी तरह से प्रीतम सिंह (अ०सा०- 10) और सज्जन सिंह (अ०सा०- 13) के साक्ष्य पर आधारित थी। अभियोजन पक्ष की ओर से स्वर्ण सिंह (अ०सा०- 11) से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वह अभियोजन पक्ष की कहानी पर वापस चले गए और अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह करने की अनुमति दी गई। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब एक गवाह, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाया गया है, को अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह करने की अनुमति दी जाती है, तो उस प्रविधि को अपनाए जाने का परिणाम उस गवाह को पूरी तरह से बदनाम करना होता है, न कि केवल उसकी गवाही के एक हिस्से से छुटकारा पाने के लिए। खिजीरुद्दीन बनाम सम्राट देखें....."

24. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जागीर सिंह प्रफुल्लकुमार सरकार में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख नहीं करते हैं।

25. लेकिन फिर बाद के एक फैसले में (जिसमें न्यायमूर्ति भगवती भी एक हिस्सा थे) यानी सैट पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन, (1976) 1 एस.सी.सी. 727, इसे अलग तरह से आयोजित किया गया था। पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति सरकारिया ने जागीर सिंह में पहले के फैसले को स्पष्ट किया, और कहा कि जागीर सिंह के मामले में जो कहा गया है वह केवल तभी लागू होगा जब एक गवाह को उस पक्ष द्वारा जिरह के माध्यम से पूरी तरह से बदनाम किया जाता है। यह केवल ऐसी स्थिति में है कि न्यायालय, विवेक के मामले में, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर देता है।

26. एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह की गवाही जिसे उस पक्ष द्वारा जिरह की गई है जिसने उसे पेश किया है, पूरी तरह से बदनाम नहीं होगा, और यह अदालत के लिए है कि इस गवाही के लिए क्या मूल्य जोड़ा जाना चाहिए। इस बिंदु पर निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद, सैट पॉल में न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"52. उपरोक्त विवेचना से, यह स्पष्ट होता है कि एक आपराधिक अभियोजन में भी जब एक गवाह से जिरह की जाती है और उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा अदालत की अनुमति का खंडन किया जाता है, तो उसके साक्ष्य को कानून के मामले के रूप में, पूरी तरह से अभिलेखों से धोया नहीं जा सकता है। यह तथ्य के न्यायाधीश के लिए है कि प्रत्येक मामले में विचार करना है कि क्या इस तरह की जिरह और विरोधाभास के परिणामस्वरूप, गवाह पूरी तरह से बदनाम हो जाता है या अभी भी उसकी गवाही के एक हिस्से के संबंध में विश्वास किया जा सकता है। यदि न्यायाधीश को पता चलता है कि इस प्रक्रिया में, गवाह का श्रेय पूरी तरह से हिल नहीं गया है, तो वह गवाह के साक्ष्य को पढ़ने और उन पर विचार करने के बाद, समग्र रूप से, उचित सावधानी और देखभाल के साथ, अभिलेखों पर अन्य सबूतों के प्रकाश में, अपनी गवाही के उस हिस्से को स्वीकार कर सकता है जिसे वह विश्वसनीय पाता है और उस पर कार्य करता है। यदि किसी दिए गए मामले में, गवाह की पूरी गवाही को खारिज कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में, गवाह पूरी तरह से और पूरी तरह से

बदनाम हो जाता है, तो न्यायाधीश को, विवेक के मामले में, अपने साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए।

53. यह ऐसे मामले के संदर्भ में था, जहां जनता, अभियोजक, संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा जिरह के परिणामस्वरूप पूरी तरह से बदनाम हो गया था, कि इस न्यायालय ने जागीर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में सावधानी के उपरोक्त नियम के साथ "जिसे कानून के नियम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए" को ध्यान में रखते हुए, कहा कि ऐसे गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।

(महत्व सन्निविष्ट)

27. ऊपर उल्लिखित मामलों की जांच से पता चलता है कि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक गवाह के साक्ष्य, जिसे उस पक्ष द्वारा जिरह की गई है, जिसने उसे पेश किया है, को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है [यह भी देखें: नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी), (2023) 4 एस.सी.सी. 731]।

28. यहां यह भी उल्लेख करना उचित हो सकता है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम वर्ष 2005 द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में उप-धारा 2 जोड़ा गया था। साक्ष्य अधिनियम की संशोधित धारा 154 अब निम्नानुसार है:

154. अपने स्वयं के गवाह से पक्षकार द्वारा प्रश्न। - (1) न्यायालय, अपने विवेक से, उस व्यक्ति को अनुमति दे सकता है जो गवाह को बुलाता है कि वह उससे कोई भी प्रश्न पूछे, जिसे प्रतिकूल पक्ष द्वारा जिरह में रखा जा सकता है।

(2) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुमत व्यक्ति को ऐसे गवाह के साक्ष्य के किसी भाग पर भरोसा करने का अधिकार नहीं देगी।

(महत्व सन्निविष्ट)

29. उपरोक्त संशोधन के माध्यम से, इस न्यायालय द्वारा दोहराई गई स्थिति अब कानून में ही आ गई है।

30. साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी "शत्रुतापूर्ण" या "शत्रुतापूर्ण गवाह" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इस बहिष्करण के पीछे तर्क यह प्रतीत होता है कि "शत्रुतापूर्ण गवाह" के रूप में गवाह की घोषणा अंग्रेजी कानून के तहत एक विशिष्ट महत्व रखती है, जहां से यह शब्द व्युत्पन्न किया गया है, जहां केवल एक पक्ष को अपने स्वयं के गवाह से जिरह करने की स्वतंत्रता दी जाती है जब "शत्रुता" की ऐसी घोषणा की जाती है। भारत में स्थिति अलग है और यहां यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह किसी पक्ष को "शत्रुता" की घोषणा की परवाह किए बिना अपने स्वयं के गवाह से जिरह करने की अनुमति दे। इस न्यायालय द्वारा सैट पॉल में यह समझाया गया है:

"38. "शत्रुतापूर्ण" गवाह, "प्रतिकूल" गवाह, "प्रतिकूल" गवाह शब्दों के अर्थ पर विवाद को दूर करने के लिए, जिसने इंग्लैंड में काफी कठिनाई और राय के टकराव को जन्म दिया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के लेखकों ने सलाह दी है कि उनमें से किसी भी शब्द के उपयोग से बचा जा सकता है ताकि, भारत में, किसी पक्ष द्वारा अपने स्वयं के गवाह से जिरह करने की अनुमति गवाह को "प्रतिकूल" या "शत्रुतापूर्ण" घोषित किए जाने पर सशर्त नहीं है। चाहे वह धारा 142 के तहत प्रमुख प्रश्न पूछने की अनुमति हो, या धारा 154 के तहत ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति हो जो प्रतिकूल पक्ष द्वारा जिरह में रखे जा सकते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस मामले को पूरी तरह से अदालत के विवेक पर छोड़ देता है (बैकुंठ नाथ बनाम प्रसन्नमोयी में सर लॉरेंस जेनकिंस की टिप्पणियां देखें, [ए.आई.आर. 1922 पीसी 409: 72 आईसी 286])। अदालत को धारा 154 द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार अयोग्य और अनियंत्रित है और "शत्रुता" के किसी भी प्रश्न से अलग है। यह उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए जब भी अदालत गवाहों के आचरण, स्वभाव, रवैया, असर, या उसके उत्तरों की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से, या उसके पिछले असंगत बयान के अवलोकन से, या अन्यथा, सोचती है कि इस तरह की अनुमति का अनुदान सत्य निकालने और न्याय करने के लिए समीचीन है। इस तरह की अनुमति प्रदान करना गवाह की सत्यता के रूप में अदालत द्वारा निर्णय के बराबर नहीं है। इसलिए, इस तरह की अनुमति देने वाले आदेश में, 'शत्रुतापूर्ण घोषित' 'घोषित', 'प्रतिकूल घोषित' जैसी अभिव्यक्तियों के



उपयोग से बचना बेहतर है, जिसका महत्व अभी भी ऐतिहासिक मकड़जाल से मुक्त नहीं है, जो उनके मददेनजर भ्रम और संघर्ष की भ्रामक विरासत लाते हैं, जिसने लंबे समय तक अंग्रेजी न्यायालयों को परेशान किया था।

(महत्व सन्निविष्ट)

31. वाक्यांश "शत्रुतापूर्ण गवाह" आमतौर पर आपराधिक न्यायशास्त्र और अदालती कार्यवाही में प्रयोग किया जाता है। हम भी अपने फैसले में "शत्रुतापूर्ण गवाह" शब्द का इस्तेमाल करने के दोष से बच नहीं सकते। हम इसे व्यावहारिक कारणों से करते हैं। इस मामले में "शत्रुतापूर्ण गवाह" जैसे कुछ शब्द अब हमारी कानूनी शब्दावली का एक हिस्सा हैं। कम से कम प्रस्तुत मामले में नए शब्दों या वाक्यांशों का आविष्कार करने या प्रतिस्थापित करने का कोई मतलब नहीं है, और हम इसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हालांकि, जो आवश्यक है, वह इस शब्द के अर्थ की व्याख्या करना है जैसा कि अब समझा जाना है। वाक्यांश "शत्रुतापूर्ण गवाह" का उपयोग एक गवाह के लिए किया जाने लगा है जो उस पक्ष की कहानी के विपरीत बयान देता है जिसके लिए वह गवाह है। फिर भी, क्योंकि एक गवाह ने किसी मामले के कुछ, हालांकि सभी नहीं, पहलुओं का समर्थन किया है, इसका स्वचालित रूप से मतलब यह नहीं होगा कि इस गवाह को "शत्रुतापूर्ण" घोषित किया जाना चाहिए। एक पक्ष धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के तहत अपने स्वयं के गवाह से जिरह कर सकता है, यहां तक कि "शत्रुता" की घोषणा किए बिना भी। धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के तहत जिरह पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि पक्ष, जो अपने स्वयं के गवाह से जिरह करना चाहता है, उसे न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। "शत्रुता" की घोषणा हुई है या नहीं, एक बात स्पष्ट है कि गवाह के साक्ष्य, जिनसे धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे गवाह को बुलाने वाले पक्ष द्वारा जिरह की गई है, को पूरी तरह से धोया नहीं जा सकता है और यह न्यायालय को देखना है कि इस तरह के सबूतों से क्या प्राप्त किया जा सकता है।

32. इसे दूसरे पहलू से समझा जा सकता है। अब हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए "साक्ष्य" शब्द की परिभाषा का उल्लेख करेंगे। यह इस प्रकार है:

"साक्ष्य" - "साक्ष्य" का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-



(1) सभी बयान जो न्यायालय जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में गवाहों द्वारा उसके समक्ष किए जाने की अनुमति देता है या करने की आवश्यकता है; ऐसे बयानों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है;

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित सभी दस्तावेज; ऐसे दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।

(महत्व सन्निविष्ट)

33. अदालत में एक गवाह द्वारा दिए गए बयान, जिसमें जिरह भी शामिल है, या तो विरोधी पक्ष द्वारा या गवाह पेश करने वाले पक्ष द्वारा आयोजित किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत 'साक्ष्य' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह साक्ष्य इसकी अनुमति से न्यायालय के समक्ष आया है। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट रोक नहीं है जो यह अनिवार्य करता है कि इस तरह के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह पूरे साक्ष्य का हिस्सा होगा जिसे न्यायालय अपने निर्णय पर पहुंचते समय जांच कर सकता है, और यह न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि उस साक्ष्य को क्या मूल्य दिया जाना है या किसी दिए गए मामले में इस तरह के साक्ष्य का उपयोग कैसे किया जाना है।

34. एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, अभियोजन पक्ष के गवाह की पूरी गवाही की अस्वीकृति, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गई है, न केवल अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि शायद किसी दिए गए मामले में बचाव पक्ष को भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आज कानून है, ऐसे गवाह की गवाही का लाभ अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों द्वारा लिया जा सकता है, जिससे उन्हें अपना मामला बनाने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिलती है [देखें: पॉलमेली बनाम टीएन राज्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 90, रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 5 एस.सी.सी. 777]। किसी भी मामले में, अंततः, यह न्याय का कारण होगा जो पीड़ित होगा यदि ऐसे गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। इसलिए, इस तरह की गवाही के साक्ष्य मूल्य का परीक्षण करना न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है।



35. यहां, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 पर भी ध्यान दे सकते हैं जो एक पक्ष, न्यायालय की अनुमति से, उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने स्वयं के गवाह की विश्वसनीयता पर महाभियोग लगाने की अनुमति देता है।

36. हालांकि यह तुच्छ और बहुत अधिक है, लेकिन कहावत "उनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस", हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पर लागू नहीं होती है। यह न्यायालय का काम है कि वह शत्रुतापूर्ण गवाह के बयानों से निपटते समय गेहूं को भूसी से अलग करे। अदालतें एक शत्रुतापूर्ण गवाह के बयान के उस हिस्से पर भरोसा कर सकती हैं जो अभिलेखों पर अन्य सबूतों द्वारा पुष्टि की जाती है। इस न्यायालय ने भज्जू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी. 327 ने निम्नलिखित शब्दों में एक शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य के मूल्य पर चर्चा की:

"36. यह स्थापित कानून है कि अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण गवाहों के साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिस हद तक वह घटना के अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करता है। ऐसे गवाहों के साक्ष्य को अभिलेखों से धोए हुए नहीं माना जा सकता है, यह मुकदमे में स्वीकार्य रहता है और इस तरह की गवाही के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है, यदि अन्य विश्वसनीय सबूतों द्वारा पुष्टि की जाती है।

यदि एक शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य का हिस्सा अन्य विश्वसनीय सबूतों के साथ पुष्टि करता है, तो साक्ष्य का वह हिस्सा स्वीकार्य है। एक बार जब अभियोजन पक्ष के गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाता है और फिर अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की जाती है, तो यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह गवाही की सत्यता का मूल्यांकन करे। गवाह के मुकर जाने के कई कारण हो सकते हैं और अदालत को एक शत्रुतापूर्ण गवाह द्वारा दिए गए सबूतों का मूल्यांकन करते समय इन कारकों पर भी गौर करना चाहिए। अभियोजन पक्ष के गवाह का मुकर जाना हमारी आपराधिक अदालतों में एक असहज वास्तविकता है। लेकिन फिर विचारण न्यायालय का उद्देश्य मामले की सच्चाई तक जाना है। अदालत के सामने जो भी सबूत हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए, पुष्टि की जानी चाहिए (जब भी आवश्यक हो), इससे पहले कि अंतिम रूप से फैसला दिया जा सके।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31. इस गवाह की गवाही में हमने जो तथ्य देखे हैं, वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ममता जीवित थी जब अ०सा०-1 और परिवार के अन्य सदस्य उसके ससुराल पहुंचे थे। इनसे यह भी पता चलता है कि ममता ने अपीलकर्ताओं के बारे में बात की थी, जिससे उसे जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था। इस गवाह ने अपने कटघरे में इस स्थिति पर वापस जाकर कहा कि ममता की मौत हो चुकी है, जब वे उसके ससुराल पहुंचे। उनकी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य के बारे में उनका रुख उनकी जिरह के अंत में एक स्पष्ट स्वीकृति से गलत साबित होता है, जहां वह कहते हैं कि यह घटना ममता के ससुराल वालों के घर हुई थी, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में, जब इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपीलकर्ताओं के पक्ष में बोल रहा था, क्योंकि उसने उनके साथ समझौता किया था, तो यह तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि डॉक साक्ष्य में उसका पूरा दोषमुक्ति का रुख झूठ की इमारत पर आधारित है। हालांकि, इस गवाह ने प्राथमिकी की सामग्री की पुष्टि करते हुए और यह स्वीकार करते हुए सच कहा है कि ममता जीवित थी जब गवाह और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके ससुराल पहुंचे और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्राथमिकी की सामग्री की पुष्टि, इस तथ्य की स्वीकारोक्ति के साथ कि ममता जीवित थी और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस गवाह के अनुसार, ममता ने उसे जहर दिए जाने के बारे में तथ्य से अवगत कराया था, जब यह गवाह उसके ससुराल में पहुंचा। यदि हम इस गवाह के साक्ष्य को उसके अंकित मूल्य पर सरसरी तौर पर लेते हैं, तो स्पष्ट रूप से सामने आने वाले भयानक सत्य की अनदेखी करते हुए, हम अपीलकर्ताओं के साथ समझौते के परिणामस्वरूप, इस गवाह द्वारा अपनाए गए झूठ की अनुमति देंगे, जो कि जो भी प्रेरणा हो, सत्य को ढकने और एक भीषण हत्यारे को बिना सजा दिए जाने की अनुमति देने के लिए।

32. अगला जिस पर हम विचार करते हैं वह अ०सा०-2 की गवाही है, जो इस मामले में स्टार गवाह है। वह मृतक की बहन है और उसी घर की रहने वाली है, जहां अपराध किया गया था। वह एक चश्मदीद गवाह है।

33. प्राथमिकी इस तथ्य को दोहराती है कि इस गवाह, जो निस्संदेह अपराध स्थल पर मौजूद थी, ने घटना को देखा था और अपने पिता को टेलीफोन पर इस तथ्य से अवगत कराया था कि ममता को उसके पति, ससुर, सास और भाभी ने जहर पीने के लिए मजबूर किया था। उसने अपने डॉक साक्ष्य में दोषसिद्धि की बात की है, यानी उसकी मुख्य परीक्षा में। यह ध्यान दिया



जाना चाहिए कि जांच के दौरान, यह गवाह अभियोजन पक्ष के मामले में खड़ा था कि यह अपीलकर्ता थे, जिन्होंने मृतक को जहर खाने के लिए मजबूर किया था, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वह अदालत में गवाही देते हुए अपराध के बारे में सभी तथ्यों पर वापस चली गई, जिसे उसने देखा था। अ०सा०-2 ने आम तौर पर यह कहने के अलावा कि उसकी बहन को दहेज की मांग के संबंध में कभी भी क्रूरता, शारीरिक या मानसिक रूप से नहीं किया गया था, ने विशेष रूप से इस तथ्य से इनकार किया है कि उसकी बहन को उसके ससुराल वालों द्वारा जहर खाने के लिए मजबूर करके मौत के घाट उतार दिया गया था। अ०सा०-2 की गवाही का संक्षिप्त और प्रासंगिक हिस्सा, जो 21.10.2020 को उसकी मुख्य परीक्षा में दर्ज किया गया था, मैं लिखा है:

"घटना दिनांक 30.7.2019 की है। मेरी बहन की मृत्यु हो गयी थी। मेरी बहन को जबरन जहर खिलाकर तेजवीर नानकराम व मुन्नी देवी ने नहीं मारा।"

34. अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा है:

"मेरी ससुराल में खेती का कार्य होता है। खेती में लगाने के लिये कोई दवा घर पर नहीं लाते हैं। ममता के साथ हुई घटना की सूचना फोन पर अपने पिता जी को दी थी।

मैंने अपने पिताजी को फोन पर बताया था कि ममता की तबीयत खराब है आप आ जाओ। मेरी सूचना पर मेरे पिताजी आदि परिवारीजन मेरे मायके से ससुराल गंगागढ़ आ गये थे और ममता को इलाज हेतु अलीगढ़ अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में अतरौली के पास ममता ने दम तोड़ दिया।

यह कहना गलत है कि मैंने ममता के साथ घटित घटना का सारा हाल अपने मायके वालों को बताया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी बहन ममता को उसके पति तेजवीर, ससुर नानकराम, सास मुन्नीदेवी ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण जबरन जहर पिलाया हो जिससे ममता की मृत्यु हो गयी।

मेरी बहन का दाह संस्कार मायके चौगानपुर में हुआ था। मैं अपनी ससुराल में अपने पति राकेश, ससुर नानकराम व सास श्रीमती मुन्नी के साथ रह रही हूँ और अपनी ससुराल से ही गवाही देने आयी हूँ।



ससुर नानकराम व सास मुन्नी देवी के साथ आयी हूं। मेरे ससुर आज मुझे वकील साहब के चेम्बर पर ले गये थे। मुझे वकील साहब ने यह नहीं बताया कि क्या गवाही देनी है।

यह बात सही है कि इस मुकदमा के मुलजिमान से फैसला हो गया है। यह बात गलत है कि मुलजिमान से फैसला हो जाने के कारण मैं आज अपना बयान बदल रही हूं।

घटना सुबह के करीब 9-10 बजे की है। जब तक मेरे मायके वाले आये उस समय मेरी ससुराल में मेरा कोई ससुराल वाला मौजूद नहीं था और मैंने ममता की तबीयत खराब होने की बावत सूचना ससुराल वालों की दी और न ही ममता का किसी डाक्टर से इलाज कराया।

मेरी बहन मृतका ममता शादी के बाद से ही बीमार रहती थी। पता नहीं उसे क्या बीमारी थी। ममता को छोटे मोटे डाक्टर को दिखाया था किस डाक्टर को दिखाया था नाम नहीं पता है। डाक्टर को अतरौली व जरगवा दिखाया था। उसके इलाज का पर्चा न मेरे पास है और न साथ लायी हूं।

आज से पहले किसी भी पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी व्यक्ति से लिखित में अथवा मौखिक रूप से यह नहीं बताया कि ममता की हत्या के मुकदमे में मेरे ससुराल वाले निर्दोष हैं। आज प्रथम बार यह बात न्यायालय में बता रही हूं।"

35. इस गवाह ने, निस्संदेह, धारा 161 द०प्र०स० के तहत पुलिस को दिए गए अपने रुख और बयानों से पीछे हट गई है, लेकिन यह समझने के लिए कि क्या उसका कोई हिस्सा अभियोजन पक्ष का समर्थन करता है, या जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई है, उसे ध्यान में रखना होगा कि अ०सा०-2, अगर उसने घटना देखी, जैसा कि पहले सूचनाकर्ता को टेलीफोन पर रिपोर्ट किया गया था और पुलिस को बताया गया था, हितों का टकराव प्रस्तुत करता है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'शैतान और गहरे नीले समुद्र के बीच पकड़ा गया' द्वारा सबसे अच्छा वर्णित किया गया है। एक ओर, यदि उसने घटना को पहले सूचनाकर्ता या पुलिस को बताए गए तरीके से देखा होता, तो उसके सामने न्याय में सहायता करने का उच्च और महान कारण होता, जिससे उसे अपने ससुराल वालों के खिलाफ दोषी बोलने की आवश्यकता होती, और दूसरी ओर, उसकी बहन के



समान परिवार में दूसरे भाई से शादी की जाती थी, अपने ससुराल वालों को कानून की कठोर सजा से बचाने की वृत्ति और व्यक्तिगत रुचि, जो उसके पति को प्रभावित करेगी, और, हो सकता है, खुद को।

36. अ०सा०-2 की गवाही पर ध्यान से देखने से पता चलता है कि उसकी मुख्य परीक्षा में, उसने कहा है कि यह घटना 30.07.2019 की है। उसकी बहन की मृत्यु हो गई। उसकी बहन को जहर खाने के लिए मजबूर नहीं किया गया और तेजवीर, नानकराम और मुन्नी देवी ने उसकी हत्या कर दी। अब, यह कथन, मुख्य परीक्षा में देखा जाता है, अपने आप में एक विचित्रता है। यह कहने से परे है कि परीक्षा-प्रमुख के दौरान, हालांकि गवाह को पेश करने वाले पक्ष द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है, इस मामले में, अभियोजन पक्ष में, गवाह को कोई प्रमुख प्रश्न या सुझाव नहीं दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि राज्य की ओर से अधिवक्ता ने कभी भी अ०सा०-2 से नहीं पूछा होगा, अगर मृतक को उसके पति, ससुर और सास ने उसे जहर खाने के लिए मजबूर करके मार डाला था। इस तरह के प्रश्न या सुझाव को न्यायालय द्वारा कभी भी अनुमति नहीं दी गई होगी। इस गवाह से बस इतना ही पूछा गया होगा कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। ममता की मौत कैसे हुई, इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके बजाय, वह अपने ससुराल वालों के लिए एक दोषमुक्ति बयान लेकर आई है कि उन्होंने उसकी बहन को जहर खाने के लिए मजबूर करके नहीं मारा। मुख्य परीक्षा में इस तरह का स्टैंड ट्यूशन और प्री-मेडिटेशन का संकेत देता है।

37. अपनी जिरह में, गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता को टेलीफोन पर ममता के बारे में "घटना" के बारे में सूचित किया था। पिता को जो कुछ भी बताया गया था, वह प्राथमिकी में लिखा गया है, जो उनके डिक्टेशन पर लिखा गया था और बाद में दर्ज किया गया था। प्राथमिकी की सामग्री को अ०सा०-2 द्वारा साबित कर दिया गया है। हालांकि, प्राथमिकी में पहले सूचनाकर्ता ने जो रिपोर्ट की थी, उसके विपरीत, गवाह ने कहा है कि उसने अपने पिता से कहा कि ममता अस्वस्थ है और उन्हें उनके स्थान पर आना चाहिए। उसने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि उसकी सूचना पर उसका परिवार उसके घर आया और वे ममता को इलाज के लिए अलीगढ़ अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अतरौली में उसकी मौत हो गई। उन्होंने अपनी जिरह में आगे कहा है कि यह कहना सही है कि इस मामले में अपीलकर्ताओं के साथ समझौता हो गया है। उसने अपनी जिरह में आगे कहा है कि 'घटना' सुबह 9-10 बजे के

बीच हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं है कि घटना क्या थी। वह आगे कहती हैं कि जब तक उनके माता-पिता पहुंचे, तब तक उनके ससुराल वालों से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। उसने आगे कहा है कि उसने अपने ससुराल वालों को सूचित किया था कि ममता अस्वस्थ है, लेकिन वे उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे।

38. गवाह ने यह भी कहा है कि ममता शादी के बाद बीमार रहेगी और उसे नहीं पता कि उसकी बीमारी क्या थी। मृतक विभिन्न डॉक्टरों से सलाह लेती थी, लेकिन वह उनके नाम नहीं जानती। अतरौली और जरगावन के डॉक्टरों से सलाह ली गई। गवाह ने यह भी कहा कि उसके पास मृतक से संबंधित कोई पर्ची नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि अदालत में उसकी गवाही दर्ज होने से पहले, उसने कभी भी मौखिक बयान नहीं दिया था या किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं किया था कि जहां तक ममता की हत्या के मामले का सवाल है, उसके ससुराल वाले निर्दोष हैं। उसने तब स्पष्ट रूप से कहा है कि यह पहली बार है कि वह अदालत में दोषमुक्ति बोल रही है।

39. यदि इस गवाह के साक्ष्य को इस संदर्भ में पढ़ा जाता है कि अभियोजन पक्ष कैसे शुरू हुआ और उनका मामला क्या था, तो सबसे महत्वपूर्ण, जो उसकी गवाही से स्पष्ट है, वह यह है कि वह सच बोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए गवाही दे रही है। यही कारण है कि उसने अपनी परीक्षा में बिना किसी उकसावे के और संदर्भ से हटकर गवाही दी है कि उसकी बहन को तेजवीर, नानकराम और मुन्नी देवी द्वारा जहर खाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि अपने पूरे साक्ष्य में, इस गवाह ने अपनी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में 'घटना' शब्द बोला है, यह दर्शाता है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि अपराध की प्रकृति में कुछ घटना हुई थी। यदि कोई अ०सा०-2 की गवाही को अंकित मूल्य पर लेता है, जहां उसने कहा है कि ममता बीमार थी और यह वह तथ्य है जो उसने अपने पिता को बताया था, तो ममता की "बीमारी" को "घटना" के रूप में वर्णित करने का कोई अवसर नहीं था।

40. 'घटना' शब्द एक बार की पर्ची नहीं है। उसने कम से कम दो बार सकारात्मक और प्रासंगिक रूप से इस शब्द का उल्लेख किया है, जो किसी अपराध के संदर्भ का संकेत देता है। उसने इस तथ्य का खुलासा किया है कि उसने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसकी गवाही हिंदी में दर्ज की गई है, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में घटना के लिए इस्तेमाल



किया जाने वाला शब्द 'घटना' है और जो कुछ भी हुआ, उसका सबसे स्पष्ट वर्णन है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, जहां वह कहती है 'घटना सुबह के 9-10 बजे की है'। अगर ममता सुबह 9-10 बजे के बीच बीमार पड़ जाती तो कोई भी शुद्ध हिंदी या स्थानीय भाषा बोलने वाला व्यक्ति इसे 'घटना' नहीं कहता। गवाह द्वारा यह वर्णन सत्य का कथन है, जिसका सार छिपा हुआ है और स्वार्थ, आत्म-संरक्षण, परिवार के भविष्य, जहां गवाह विवाहित है और इसी तरह से प्रेरित झूठ से ग्रहण किया गया है; एक साधारण व्यक्ति के सभी व्यावहारिक विचार, एक असाधारण या संत चरित्र के अधिकारी नहीं।

41. हमारे इस निष्कर्ष को इस तथ्य से पुष्ट किया जाता है कि उसने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि यह सच है कि अपीलकर्ताओं के साथ समझौता किया गया है। यदि ममता अभी-अभी बीमार हुई थी और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी, तो एक संभावना है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया था, कि मामला मृतक के पिता द्वारा पैसे ऐंठने के लिए प्रेरित किया गया था और जिस समझौते की बात की गई थी, उसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि ऐसा होता, तो बचाव पक्ष निश्चित रूप से अ०सा०-1 को उस संदर्भ के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछता, जिसमें आरोप लगाए गए थे, जिसके जवाब में, अपरिवर्तनीय रूप यह होता कि प्राथमिकी किसी गलत धारणा या भ्रमक प्रभाव में दर्ज की गई थी।

42. कोई सांसारिक कारण नहीं है कि पहला सूचनाकर्ता अ०सा०-2 से एक विशिष्ट जानकारी का उल्लेख करेगा कि मृतक को उसके ससुराल वालों और पति द्वारा जहर निगलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और फिर पुलिस को रिपोर्ट करेगा कि उसने अपनी बेटी को जहर से मरते हुए पाया, जिसे वह अस्पताल ले गया, लेकिन सफल नहीं हो सका क्योंकि वह रास्ते में मर गया। तथ्य यह है कि उपरोक्त प्रभाव के आरोपों के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई थी; तथ्य यह है कि अ०सा०-2 की गवाही में, मृतक के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे अचानक बीमारी की शुरुआत के बारे में कुछ भी कहे बिना एक घटना के रूप में उल्लेख किया गया है; तथ्य यह है कि इस गवाह द्वारा प्रथम सूचना संस्करण के इतने हिस्से की पुष्टि की जाती है कि ममता को पहले सूचनाकर्ता द्वारा अलीगढ़ में स्थित अस्पताल ले जाया जा रहा था, न कि उसके ससुराल वाले, जब उसकी अंतरौली में रास्ते में मृत्यु हो गई; तथ्य यह है कि अ०सा०-2 की गवाही से पता चलता है कि पक्षगण के बीच एक समझौता हो गया है; तथ्य यह है कि अ०सा०-2 ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना सुबह लगभग 9-10 बजे हुई थी और जब उसके माता-पिता पहुंचे,



तो ससुराल वाले बाहर थे; तथ्य यह है कि ममता को उसके पति या ससुराल वालों द्वारा अस्पताल नहीं ले जाया गया था, अगर वह अस्वस्थ थी, जो इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है; तथ्य यह है कि अ०सा०-2 ममता जिस बीमारी से पीड़ित थी, उसके प्रकार या प्रकृति के बारे में मायावी है, जिसे उसने मृत्यु का कारण दिखाने के लिए अपनी जिरह में उद्धृत किया है; और, तथ्य यह है कि अ०सा०-2 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अतीत में उसने कभी भी किसी प्रशासनिक अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप में नहीं बताया था कि उसके ससुराल वाले निर्दोष थे, स्पष्ट रूप से अभिलेखों में ऐसे तथ्य लाते हैं जो अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा करते हैं।

43. गवाह की गवाही का दोषमुक्ति वाला हिस्सा, हालांकि बोल्ड और सकारात्मक है, ऊपर देखे गए तथ्यों के सामने अदालत के साथ विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, जो इस फैसले में बाद में ध्यान देने योग्य अन्य तथ्यों के अलावा हानिकारक हैं।

44. अब हम अ०सा०-3 की गवाही पर विचार कर सकते हैं, जिसने भी दोषमुक्त करने की कोशिश की है। अ०सा०-3 ममता की मां है। उसने जांच के दौरान पुलिस के सामने कभी भी दोषमुक्ति नहीं की, लेकिन अपने गोदी में पहली बार ऐसा किया। अपनी मुख्य परीक्षा में, इस गवाह ने कहा है:

'दिनांक 30/7/2019 को मेरी बेटी ममता की मृत्यु हो गयी, जिसकी खबर हमें मेरी छोटी बेटी चन्द्रवती ने फ़ोन पर दी थी। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ममता को जहर देकर किसने मारा। मेरी बेटी के पति, ससुर नानकराम, सास श्रीमती मुंदनी देवी ने मेरी बेटी को जहर देकर नहीं मारा। ये लोग निर्दोष हैं।'

45. अपनी जिरह में, अ०सा०-3 ने गवाही दी है:

"घटना की खबर सुनकर मैं व मेरे परिवार वाले अपनी बेटियों की ससुराल गंगागढ़ गये थे। गंगागढ़ में जाकर हमने देखा कि मेरी बेटी ममता की तबीयत ज्यादा खराब थी। थोड़ा-2 बोल पा रही थी। हमारी अपनी छोटी बेटी चन्द्रवती से बातचीत हुई तो रोने धोने लगी। मेरी बेटी के ससुराल वाले घर पर मौजूद थे। हमें देखकर वहाँ से चले गये। फिर हम लोग बेटी ममता को इलाज के लिए अलीगढ़ अस्पताल ले जा रहे थे कि अतरौली के पास उसने दम तोड़ दिया।"



यह बात सही है कि इस घटना के बाबत मेरे पति ने मेरी बेटी ममता के पति सास ससुर व ननद के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। यह बात सही है कि मुल्जिमान से हमारा समझौता हो गया हो। यह बात गलत है कि फैसला हो जाने के कारण मैं बयान बदल रही हूँ। मेरी बेटी बीमार नहीं रहती थी और ठीक ठाक थी। मेरी बेटी के साथ जो भी घटना घटी वह उसकी ससुराल में घटी थी। घटना के समय मैं मौजूद नहीं थी। इसलिये मैं नहीं बता सकती कि उसको जहर देकर किसने मारा था। यह भी नहीं बता सकती कि उसके पति सास ससुर व ननद ने जहर दिया था या अपने स्वयं खाया था। मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरी बेटी का पति इस मुकदमा में काफी दिनों से जेल में है और मेरी बेटी के सास ससुर भी जेल गये थे लेकिन मैंने आज तक किसी पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी या किसी व्यक्ति को यह बात लिखित या मौखिक रूप से कभी किसी को नहीं बतायी कि मेरी बेटी के ससुराल वाले इस मुकदमे के मुल्जिमान कतई निर्दोष हैं। उन्होंने मेरी बेटी को जहर देकर नहीं मारा। आज मैं यह बात सर्वप्रथम कह रही हूँ। यह बात सही है कि इस मुकदमा के मुल्जिमान ने जब न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे तो मेरे पति ने जमानत का अपने अधिवक्ता से विरोध करवाया था।

घटना के समय मेरी बेटी चन्द्रवती घटनास्थल पर मौजूद थी जिसने घटना अपनी आँखों से देखी थी तथा हमें सूचित किया था। यह कहना गलत है कि चन्द्रवती के भविष्य की खातिर हम लोगों ने उसके ससुराल वालों से इस मुकदमा में फैसला ना लिया हो और आज मैं मुल्जिमान को बचाने के लिए उनसे मिलकर कानूनी सलाह मशवरा से झूठी गवाही दे रही हूँ और सही बात को छिपा रही हूँ।"

46. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर, अ०सा०-3 ने कहा:

'मेरी बेटी ममता अक्सर बीमार रहती थी। दवाई चलती रहती थी। मेरी बेटी ममता का इलाज उसके ससुराल वालों द्वारा कराया जाता था। मेरी बेटी ममता गुस्सैल व चिड़चिड़े स्वभाव की थी। छोटी-छोटी बातों पर मरने को तैयार हो जाती थी। शादी से पहले भी कई बार उसने आत्महत्या का प्रयास किया था।"



47. इस गवाह की गवाही, किसी भी तरह से, रहस्यमय नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया है, जो अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में संदेह पैदा करता है। यह जितना छिपाता है उससे कहीं अधिक प्रकट करता है। यह अ०सा०-3 द्वारा अपनी दूसरी बेटी के हित में न्याय को हराने का एक असभ्य प्रयास है, जिसकी शादी अपीलकर्ता के परिवार में दूसरे बेटे से हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वह मकसद है जिसने मृतक के परिवार को अपीलकर्ताओं के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित किया है, यानी अदालत में झूठ बोलने के लिए समझौता करना और अपीलकर्ताओं को कानून की सजा से बचाना।

48. हमने अ०सा०-3 की गवाही पर ध्यान से गौर किया है। अ०सा०-2 की तरह, उसकी परीक्षा-प्रभारी एक गप्पी बैनर से शुरू होती है कि गवाह अपीलकर्ताओं को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इस गवाह ने कहा है कि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी ममता को किसने जहर देकर मार डाला था। इसके बाद वह कहती है कि ममता को उसके पति तेजवीर, ससुर नानकराम और सास मुन्नी देवी ने जहर नहीं दिया था। ये लोग निर्दोष हैं। अब, जैसा कि अ०सा०-2 के मामले में होता है, किसी ने भी इस गवाह से कोई प्रमुख प्रश्न नहीं पूछा होगा या उसे इस तरह का सुझाव नहीं दिया होगा, उसे यह कहने के लिए आमंत्रित किया होगा कि अपीलकर्ता निर्दोष थे। उनकी मुख्य परीक्षा के लहजे और कार्यकाल से पता चलता है कि वह अपीलकर्ताओं के पक्ष में झूठ बोलने और उन्हें सजा से बचाने के लिए प्रेरित थीं।

49. इस गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसकी बेटी के ससुराल से घटना की खबर मिलने पर परिवार गंगागढ़ चला गया। वहां उन्होंने देखा कि ममता की तबीयत बहुत खराब है। वह कमजोर बोल सकती थी। मृतक के ससुराल वाले मौजूद थे, लेकिन माता-पिता और मृतक के परिजनों को देखकर वे वहां से चले गए। इस पर, गवाह का कहना है कि वे (ममता के माता-पिता और परिवार) उसे अलीगढ़ अस्पताल ले जा रहे थे, जब रास्ते में अटरौली में उसकी मौत हो गई।

50. इन तथ्यों से पता चलता है कि कुछ हिंसा या अपराध हुआ, जिससे ममता प्रभावित हुई, और ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ अस्वस्थ थी जैसा कि इस अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया था। वरना ममता के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे 'घटना की खबर सुनकर मैं वा मेरे परिवार वाले.....' शब्दों में बयां करने का कोई कारण नहीं था। अ०सा०-3 की गवाही हिंदी में दर्ज है, जिसे वह बोलती है। कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति किसी भी तरह की



कल्पना से किसी बीमारी को एक घटना (घटना) के रूप में वर्णित नहीं करेगा। यह केवल एक अपराध है, जिसका वर्णन इन शब्दों में किया गया है। गवाह की गवाही का यह हिस्सा अभियोजन पक्ष के लिए बहुत प्रासंगिक है, जिस पर हम ध्यान देने के लिए बाध्य हैं।

51. आगे की बात यह है कि ममता के ससुराल वाले मुंह पलट कर चले गए, हालांकि वहां, जब उन्होंने अपने माता-पिता और परिवार को आते देखा। यह, किसी भी तरह से, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है, अगर उनकी बहू अस्वस्थ थी और उसके माता-पिता उसका कल्याण करने आए थे। यह प्रतिक्रिया एक जुझारू दिमाग और एक दोषी विवेक की कहानी है, जो मरने वाले पीड़ित के लिए नफरत से भरी है। यदि मृतक बीमार थी, जैसा कि अपीलकर्ताओं का आग्रह है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो सूचनाकर्ता और उसके परिवार के लिए, जैसा कि अंसा०-3 कहता है, उसे चिकित्सा सहायता के लिए अलीगढ़ के एक अस्पताल में ले जाने का कोई कारण नहीं था। अगर ममता बीमार होती, तो उसके ससुराल वाले उसे अस्पताल ले जाते, या कम से कम, इलाज के लिए ममता के माता-पिता के साथ अलीगढ़ जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं था।

52. अंसा०-3 की गवाही में आगे का स्पष्ट तथ्य यह है कि वह स्वीकार करती है कि सूचनाकर्ता ने अपीलकर्ताओं के साथ समझौता किया था। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि समझौता किस बारे में था और किन परिस्थितियों में इसमें प्रवेश किया गया था। यह यह भी खुलासा नहीं करता है कि समझौते के लिए क्या विचार किया गया था और मुखबिरों को पक्षगण के बीच समझौते के संदर्भ में क्या करना चाहिए था। जाहिर है, समझौता अपीलकर्ताओं को कानून की सजा से बचाने के लिए था, सूचनाकर्ता के लिए संभावित विचार यह था कि उनकी दूसरी बेटी अभी भी शादीशुदा थी और अपीलकर्ताओं के परिवार में रह रही थी। अपीलकर्ताओं के लिए एक दोषसिद्धि, अगर यह गवाह और ममता के परिवार के अन्य सदस्यों, जिन्होंने दोषमुक्ति की गवाही दी है, सच बोलते हैं, तो दूसरी बेटी की शादी के लिए कयामत की भविष्यवाणी कर सकते और उसके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देते। कुछ अन्य विचार भी हो सकते हैं, जिसे हम पूछताछ करने के लिए शुरू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें यकीन है कि गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता निर्दोष थे और उसने अपनी बेटी को जहर देकर हत्या नहीं की, झूठ बोल रहा है। तथ्य जो उसने अन्यथा कहा है, वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह अपीलकर्ता थे, जिन्होंने अपराध किया था जिसे उसने एक 'घटना' के रूप

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में वर्णित किया है, जिससे मृतक का परिवार उसके ससुराल में भाग गया और उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया।

53. अपनी जिरह में इस गवाह के साक्ष्य पर एक और नज़र डालने से पता चलता है कि वह बार-बार अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक घटना (घटना) के रूप में संदर्भित करती है और कहती है कि जब घटना हुई, तो वह वहां मौजूद नहीं थी। वह तो यहां तक कह चुकी है कि उसे नहीं पता कि उसे किसने जहर देकर मार डाला। उसने आगे गवाही दी है कि वह यह नहीं कह सकती कि उसकी बेटी के पति, ससुर, सास या भाभी ने उसे जहर दिया या उसने खुद जहर खाया। तब इस गवाह ने कहा कि उसे पता है कि उसकी बेटी का पति इस मामले में जेल में है और उसके ससुर और सास भी जेल गए थे। अ०सा०-3 तब अपनी जिरह में कहती है कि उसने कभी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से नहीं कहा है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से निर्दोष थे, और उन्होंने उसकी बेटी को जहर नहीं दिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि यह पहली बार था कि वह अपने गोदी साक्ष्य में दोषसिद्धि बोल रही थी। इस गवाह से जो सबसे स्पष्ट गवाही मिलती है, वह इस आशय की है कि यह सही था कि अपीलकर्ताओं, जब उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था, तो गवाह के पति, यानी अ०सा०-1 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका का विरोध किया था। अ०सा०-3 के साक्ष्य का यह हिस्सा इसे स्पष्ट बनाता है, जैसा कि हमने पहले ही अलग तरह से कहा है, कि वह औपचारिकता के लिए दोषसिद्धि बोल रही है, जो पक्षगण के बीच तथाकथित समझौते से प्रेरित है। अन्यथा, जिन तथ्यों की उसने गवाही दी है, वे अपीलकर्ताओं की बेगुनाही के अनुरूप नहीं हैं।

54. अ०सा०-3 ने अपनी जिरह के इस भाग में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी बेटी को जहर देकर मार डाला गया था। उसे नहीं पता था कि उसके पति या ससुराल वालों ने उसे जहर दिया या उसने खुद इसका सेवन किया। यह गवाही इस बात को स्पष्ट करती है कि अन्य गवाहों द्वारा ममता की मृत्यु के बारे में मायावी बने रहने का या यह कहने का कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई, स्पष्ट रूप से गलत है। अ०सा०-3 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसे पता था कि ममता की मृत्यु जहर के कारण हुई है। उसने यह कहकर अपीलकर्ताओं के लिए स्थिति को उबारने का प्रयास किया है कि वह नहीं जानती कि ममता को किसने जहर दिया, चाहे वह उसका पति हो या ससुराल वाला, या उसने खुद इसका सेवन किया।



55. तथ्य के चौथे गवाह, यानी अ०सा०-4 बंती सिंह, मृतक के भाई की गवाही पर ध्यान देना भी उचित होगा। अपनी मुख्य परीक्षा में, अ०सा०-4 ने निम्नलिखित प्रभाव की गवाही दी है:

'मेरी बहन ममता की मृत्यु 30.7.2019 को जहर पीने से हो गयी। घटना की सूचना हमें मेरी छोटी बहन चन्द्रवती ने मेरे पिता को दी थी। मेरी बहन को उसके पति तेजवीर, सास मुंदनी देवी व ससुर नानकराम व ननद रामा ने जबरन जहर नहीं दिया। और न ही जहर देकर मेरी बहन को मारा।'

56. गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गई। अपनी जिरह में, अ०सा०-4 ने इस प्रकार कहा है:

"घटना की खबर सुनकर हम सभी लोग अपनी बहनो की ससुराल ग्राम गंगागढ़ पहुँचे थे। घटना का सारा हाल चन्द्रवती ने हम लोगो को बता दिया था। फिर हम लोग ममता को इलाज के लिए अलीगढ़ ले जा रहे थे कि रास्ते मे मेरी बहन ममता ने दम तोड़ दिया। रास्ते मे भी हमारी ममता व चन्द्रवती से घटना की बाबत बाते होती गयी थी।

ममता की मृत्यु के बाद इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता चोखेलाल ने मुझसे बोल-2 कर लिखायी थी। जो मेरे पिता ने बोला था वही मैंने तहरीर में लिख दिया था। फिर मैंने तहरीर अपने पिता को पढ़कर सुनायी तब मेरे पिता के उस पर अपने हस्ताक्षर कर थाना रामघाट पर दी थी। वह असल तहरीर आज पत्रावली पर प्रदर्श क-1 के रुप मे उपलब्ध है जो मेरे लेख मे है।

यह बात सही है कि घटना के समय मेरी छोटी बहन चन्द्रवती मौजूद थी और उसने सारी घटना देखी थी। यह सही है कि मुल्जिमान से हमारा राजीनामा हो गया है लेकिन राजीनामा के कारण आज मैं झूठी गवाही देकर बयान दे रहा हूँ यह गलत है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि इस मुकदमा में मेरे बहनोई तेजवीर जेल में है और मेरी बहन के सास ससुर भी जेल गये थे।

यह सही है कि मैंने आज तक कहीं भी किसी भी आला अधिकारी या व्यक्ति को यह नहीं बताया कि मेरी बहन के ससुराल वाले इस मुकदमे में निर्दोष हैं। आज मैं सर्वप्रथम यह बात न्यायालय में कह रहा हूँ।



57. यह गवाह भी अपनी परीक्षा-प्रधान में गवाही के उस अजीब टुकड़े के साथ सामने आया है, जहां एक जिरह परीक्षक के नेतृत्व में या किसी भी प्रकार के सुझाव के तहत, उसने अचानक कहा है कि उसकी मृत बहन के पति, सास और ससुर ने उसे जबरन जहर नहीं दिया, न ही उन्होंने उसे इस तरह से मार डाला। जैसा कि पहले ही एक अन्य गवाह की गवाही के संबंध में कहा जा चुका है, कोई भी अ०सा०-4 को अपीलकर्ताओं के बारे में दोषमुक्ति देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था, जिस तरह से उसने अपनी परीक्षा-इन-चीफ में किया है। मुख्य परीक्षा में, हालांकि गवाह पेश करने वाले पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है, इस मामले में अभियोजन पक्ष के लिए, किसी भी प्रमुख प्रश्न को अपने गवाह के सामने रखने की अनुमति नहीं है। इसलिए, राज्य के अधिवक्ता ने कभी भी अ०सा०-4 से नहीं पूछा होगा कि क्या मृतक को उसके पति, ससुर और सास ने उसे जहर खाने के लिए मजबूर करके मार डाला था। इस तरह के प्रश्न की न्यायालय द्वारा कभी अनुमति नहीं दी गई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस गवाह से बस इतना ही पूछा गया होगा कि ममता की मौत कैसे हुई। यदि यह झूठे अभियोजन का एक स्पष्ट मामला था, जहां गवाह ने समर्थन नहीं किया, तो वह दोषी ठहराने वाले तथ्यों को नहीं बोलता, लेकिन वह अपनी बहन की मृत्यु में शामिल परिस्थितियों के बारे में जो कुछ भी जानता था, वह कहता। मुख्य परीक्षा में कभी भी इस तरह का एक अजीब दावा नहीं होगा कि उसके पति या सास और ससुर ने उसे नहीं मारा। ऐसा हो सकता था यदि अ०सा०-4 को इस तरह से बोलने के लिए सिखाया और प्रेरित किया गया था, जो कि स्पष्ट रूप से यहां मामला है।

58. अपनी जिरह में, अ०सा०-4 ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि ममता जीवित थी जब उसके माता-पिता और भाई आदि उसके ससुराल में पहुंचे। उसे अलीगढ़ ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह सूचनाकर्ता के मामले को गलत साबित करता है कि ममता पहले ही मर चुकी थी जब उसका परिवार उसके ससुराल पहुंचा था। इस गवाह ने विशेष रूप से कहा था कि अस्पताल जाते समय परिवार ने ममता और चंद्रावती के साथ घटना के बारे में बात की थी। अब, अपनी जिरह के अगले चरण में, इस गवाह ने कहा है कि उसने अपने पिता के आदेश पर प्राथमिकी लिखी, जहां ससुराल वालों के खिलाफ मृतक को जहर खाने के लिए मजबूर करने के निश्चित आरोप हैं। गवाह ने इस तथ्य की भी गवाही दी है कि उसने उस प्राथमिकी को पढ़ा जो उसे लिखी गई थी और उसकी सामग्री सुनने के बाद, उसके पिता ने



उसके हस्ताक्षर किए और उसे थाना रामघाट को सौंप दिया। इस गवाह ने भी प्राथमिकी, प्रदर्शक-1 की सामग्री को देखा और पुष्टि की कि यह वही दस्तावेज है।

59. अ०सा०-4 ने आगे कहा है कि घटना के समय उसकी छोटी बहन, चंद्रावती मौजूद थी और उसने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा। इस गवाह द्वारा आगे कहा गया है कि यह कहना अटपटा है कि सूचनाकर्ता के पक्ष ने अपीलकर्ताओं के साथ समझौता किया था, लेकिन उसने यह भी कहा कि यह इस कारण से नहीं है कि वह उनके पक्ष में झूठी गवाही दे रहा था। इस गवाह की जिरह का अंतिम भाग जो मामले पर प्रकाश डालता है, जहां गवाह दूसरों की तरह कहता है, कि मुकदमे की शुरुआत से पहले, उसने कभी भी किसी उच्च अधिकारी (पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में) को इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि अपीलकर्ता निर्दोष थे और उसकी बहन के मामले में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। इस गवाह, अ०सा०-4 से भी बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई, जहां उसने इस प्रकार बात की है:

"मैं घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं हूँ। मैंने कोई घटना नहीं देखी है। सुनी हुई बातों के आधार पर ही मैं गवाही दे रहा हूँ। मेरी बहन अक्सर बीमार रहती थी। और बीमारी के कारण वह चिढ़ चिढ़े स्वभाव की हो गयी थी। काफी दवाई गोली खाती थी। बीमारी का इलाज मेरी बहन के ससुरालवालों द्वारा कराया जाता था। अधिक बीमार रहने के कारण वह डिप्रेशन में रहने लगी।

हमारी बहन के ससुरालीजन के घर पर खेती का कार्य होता है। घर पर कीटनाशक दवाई खेती में लगाने हेतु रखी रहती है। बीमारी से तंग आकर और बच्चा पैदा न होने के कारण मेरी बहन ने स्वयं घर पर रखी कीटनाशक दवायी पी और उसकी उससे मृत्यु हो गयी।"

60. यह गवाह स्वीकार करता है कि वह उस घर का निवासी या मूल निवासी नहीं है, जहां मृतक अपने ससुराल वालों और अपनी बहन के साथ रहता था। इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि उसने उस घटना को नहीं देखा जिसके कारण ममता की मृत्यु हुई, जो उसके ससुराल के चार कोनों के भीतर हुई थी। इस घटना को मृतक ने देखा था और इस गवाह की बहन, अ०सा०-2 ने भी उसी घर में ममता के पति के एक भाई से शादी की थी। इसलिए, अ०सा०-4 ने एसओएस कॉल प्राप्त होने के बाद अपनी बहन के ससुराल पहुंचने पर जो कुछ भी देखा, उसका



गवाह है, जिसे अ०सा०-2 ने अपने पिता, अ०सा०-1 के माध्यम से दिया था। इसलिए, उनकी गवाही इस तथ्य के बारे में प्रासंगिक है कि मृतक जीवित थी जब उसके माता-पिता और भाई सहित उसका परिवार उसके ससुराल पहुंचा।

61. यह उस किसी भी चीज़ के बारे में भी प्रासंगिक है जो मृतक ने अस्पताल के रास्ते में मरने से पहले अपनी मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में कहा था। मृतक ने अपने ससुराल में या रास्ते में परिवार के साथ जो कुछ भी साझा किया, उसे सुनने के बाद, साथ ही इस गवाह की दूसरी बहन से जो कुछ भी सुना, अ०सा०-1 ने एक प्राथमिकी लिखी, जिसे इस गवाह ने लिखा और इस तथ्य की गवाही दी कि उसने इसे सटीक रूप से लिखा है। प्राथमिकी की सामग्री दोषी है और ममता के ससुराल वालों के एक सटीक मामले के बारे में बताती है, जो उसे जहर खाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए, यह गवाह प्राथमिकी संस्करण की सटीकता को और स्थापित करता है। अ०सा०-4, विशेष रूप से, इस तथ्य का समर्थन करता है कि सूचनाकर्ता और उसके परिवार ने अपीलकर्ताओं के साथ समझौता किया था। केवल यह दावा कि वह समझौते के कारण अदालत में झूठ नहीं बोल रहा था, उसके वचन पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

62. परिस्थितियों की समग्रता को देखना होगा। प्राथमिकी में रुख, जिसे इस गवाह ने लिखा था और अदालत में भी साबित किया था, पुलिस को दिए गए बयान, जिसमें इस गवाह का बयान और अदालत में बदला हुआ रुख शामिल है, कुछ बाहरी विचार का संकेत देते हैं, जो अभियोजन पक्ष के मामले से अलग होने के लिए इस गवाह के दिमाग में काम कर रहे हैं। तथ्य यह है कि इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसने कभी भी किसी उच्च अधिकारी को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया कि ममता के ससुराल वाले निर्दोष थे, इस गवाह के डॉक साक्ष्य को एक शुद्ध बाद का विचार और सूचनाकर्ता और अपीलकर्ताओं के बीच कुछ अपवित्र सौदेबाजी का परिणाम दर्शाता है। इस गवाह के मामले में भी, अभियोजन पक्ष के मामले का एक स्पष्ट समर्थन मिलता है, जिसे गवाह किसी अन्य लक्ष्य की तलाश में छिपाने की कोशिश कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से न्याय के कारण की सेवा करने से अलग करता है।

63. इस गवाह की गवाही से निम्नलिखित दोषसिद्धि संबंधी तथ्य सामने आते हैं: गवाह अपने माता-पिता के साथ अपनी छोटी बहन से सुनकर ममता के ससुराल में चला गया, जिसे वह एक घटना के रूप में वर्णित करता है; दूसरे, यह तथ्य कि ममता जीवित थी जब यह गवाह पहले सूचनाकर्ता और उसकी मां के साथ उसके ससुराल में पहुंचा; तीसरा, यह तथ्य कि ममता ने इस

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गवाह, सूचनाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों से उसके ससुराल में और मरने से पहले अस्पताल जाते समय घटना के बारे में बात की थी; चौथा, तथ्य यह है कि इस गवाह की दूसरी बहन, चंद्रावती, जो उसी घर की निवासी है, ने ममता को अस्पताल ले जाते समय इस गवाह और परिवार के अन्य सदस्यों को उसके ससुराल में और रास्ते में घटना की परिस्थितियों के बारे में बताया; पांचवां, तथ्य यह है कि इस गवाह ने प्राथमिकी की सामग्री की पुष्टि की, जिसे उसने अपने पिता के डिक्टेशन पर लिखा था; छठा, तथ्य यह है कि प्राथमिकी में अपीलकर्ताओं द्वारा वहां वर्णित तरीके से अपराध करने के बारे में मजबूत आरोप लगाए गए हैं; सातवां, तथ्य यह है कि गवाह ने स्वीकार किया कि सूचनाकर्ता और अपीलकर्ताओं के बीच समझौता हुआ था; और, आठवां, तथ्य यह है कि इस गवाह ने कहा है कि उसने कभी भी किसी उच्च अधिकारी को सूचित नहीं किया कि ममता के ससुराल वाले निर्दोष थे, हालांकि वह जानता था कि उसका पति जेल में था और ससुर और सास जेल जा चुके थे।

64. इस गवाह ने पेश करने का प्रयास किया है, जब अपीलकर्ताओं द्वारा जिरह की गई है, तो सबूत का एक अतिरिक्त टुकड़ा है। समझौते के पूर्ण फल का एहसास करने के लिए स्पष्ट रूप से उनसे जिरह की गई है। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी जिरह में, उन्होंने ममता के बारे में मामला पेश किया है कि उसने अपनी बीमारी से निराश होने और इस तथ्य के कारण कि वह एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, घर पर रखे कुछ कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब, यह एक बचाव नहीं है, जिसे अपीलकर्ताओं ने धारा 313 द०प्र०स० के तहत अपनी गवाही में पेश किया है। कार्यवाही के किसी भी चरण में, अपीलकर्ताओं द्वारा इस मामले को नहीं लिया गया है। अपीलकर्ताओं द्वारा अ०सा०-4 की जिरह को एक ओर उनका बचाव नहीं माना जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर, यह दर्शाता है कि गवाह जानबूझकर अपीलकर्ताओं को पक्षों के बीच समझौते के कारण कानून के दंड से बचाने का प्रयास कर रहा था। यह तथ्य अपीलकर्ताओं की मिलीभगत को स्थापित करने के लिए काम करता है, बजाय उन्हें अपराध के परिणामों से बचाने के।

65. यहां शव परीक्षण चिकित्सक की गवाही पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जिसने अ०सा०-5 के रूप में गवाही दी है, शव परीक्षण रिपोर्ट के आवश्यक संदर्भ के साथ, पूर्व केए -2, और विश्लेषण के लिए उन्हें भेजे गए संरक्षित विसरा के बारे में उनके निष्कर्षों के बारे में विधि विज्ञान



प्रयोगशाला की रिपोर्ट। शव परीक्षण करने वाले अ०सा०-5, डॉ. अजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस प्रकार गवाही दी है:

"विसरा संरक्षित करने हेतु अमाशय, छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय गुर्दा प्लीहा के टुकड़े लेकर संग्रहित किया गया।

शव विच्छेदन के पश्चात शव विच्छेदन आख्या, वस्त्र, विसरा 6 जार सील मोहर कर शव को लाये सिपाही रिचा के सुपुर्द किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा मेरे लेख व हस्ताक्षर मे तैयार की गयी थी। जिस पर डा० अनुराग यादव के भी हस्ताक्षर अंकित है। शव विच्छेदन रिपोर्ट सं.

689/2019 प्रपत्र सं. 9A/1 ता 9A / 3 के रूप में पत्रावली पर शामिल है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्शक 2 डाला गया।

मृतका की मृत्यु कीटनाशक दवाई के सेवन से होना सम्भावित है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट उपलब्ध है। मृतका की मृत्यु दिनांक 30.7.2019 को होना सम्भव है।"

66. अ०सा०-5, अपनी जिरह के प्रासंगिक भाग में, कहा गया है:

"पी.एम. के लिए आया शव सील बन्द था सील मैंने देखी थी ठीक थी चोट नं. 1,2,3,4 मृतका के इलाज के दौरान इनजेक्शन वगैरा देने से आना सम्भव है। चोट नं. 3 व 4 जो टेप लगी मैंने देखी है वह भी इलाज के दौरान आना सम्भव है। इन चोटों के अलावा शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं थी। मृतका के शरीर पर जो चोटें थी वह डाक्टरों द्वारा इलाज कराने के दौरान आती है।

जो मृत्यु का सम्भावित समय लिखा 3/4 दिन लिखा है उसमें से 12 से 18 घंटे का अन्तराल दोनों तरफ हो सकता है।"

67. डॉक्टर की जांच के पढ़ने से पता चलता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में, उन्होंने राय दी है कि यह संभव है कि मृतक की मृत्यु विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट किए गए रासायनिक कीटनाशक के सेवन के कारण हुई हो। डॉक्टर ने

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपनी जांच में यह भी राय दी है कि मृतक की मृत्यु 30.07.2019 को हो सकती है। अपनी जिरह में, डॉक्टर से बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की गई कि क्या मृतक की मौत जहर से नहीं हुई थी। बल्कि, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मृत शरीर पर पाए गए विभिन्न घावों, यह राय प्राप्त करने के लिए एक खोज जिरह का विषय थे कि क्या वे उसकी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। डॉक्टर की जिरह से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर जो चोटें देखी गई हैं, उन्हें चिकित्सा उपचार का संभावित परिणाम कहा गया था। इसके लिए ज्यादा वजन नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि मृतक को अपने ससुराल वालों के साथ कोई चिकित्सा ध्यान नहीं दिया गया था और अलीगढ़ के एक अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जहां उसे उसके माता-पिता और परिवार द्वारा पहुंचाया जा रहा था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो शव परीक्षण रिपोर्ट में और न ही कटघरे में अपनी गवाही में, डॉक्टर ने ममता की मौत का कारण किसी भी शव परीक्षण पूर्व चोटों को जिम्मेदार ठहराया है। जिरह से पता चलता है कि डॉक्टर को वास्तव में मृतक के शरीर पर देखे गए मृत्यु पूर्व चोटों के कारण, प्रकृति और प्रभाव का पता लगाने के लिए अधिक कठोर जिरह के अधीन नहीं किया गया है। साथ ही, उन्हें उनकी राय के बारे में ज्यादा चुनौती नहीं दी गई कि मृतक की मृत्यु कीटनाशक से विषाक्तता से हुई थी, जो कि ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक के कारण संभव माना गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट में ममता की मौत के लिए शव परीक्षण से पहले की किसी भी चोट को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। अपीलकर्ताओं द्वारा डॉक्टर की जिरह के दौरान प्राप्त किसी भी तथ्य के अभाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ममता की मृत्यु का कारण ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक के कारण विषाक्तता थी।

68. हम यहां यह टिप्पणी करने के लिए रुक सकते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी स्तर पर ऐसा कोई मामला नहीं है कि ममता ने खुद का जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। धारा 313 द०प्र०स० के तहत दिए गए बयान में यह उनका मामला नहीं है। बल्कि, उनका बचाव यह है कि मृतक बीमार रहेगा और विभिन्न डॉक्टरों से इलाज की मांग करेगा। वह इसके बारे में उलझन में रहती थी। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि बचाव पक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक ने आत्महत्या की, क्योंकि वह बीमारी से व्यथित थी। हमें डर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि अपीलकर्ताओं को यह मामला लेना था कि मृतक ने आत्महत्या की है, तो उन्हें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताना होगा और उन परिस्थितियों की गणना करनी होगी, जिनमें उसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की ओर से



आत्महत्या का मामला सामने आने के अभाव में, पक्षों के बीच समझौते की पृष्ठभूमि में केवल एक दावा कि गवाह को नहीं पता था कि ममता को उसके पति और ससुराल वालों ने जहर दिया था या उसने खुद जहर खा लिया था, अपीलकर्ताओं को लाभ नहीं होगा। तथ्य के सभी चार गवाहों के साक्ष्य और चिकित्सा-कानूनी साक्ष्य को एक साथ रखा गया है, स्पष्ट रूप से दोषी तथ्य हैं, जो कम से कम अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह से परे इस हद तक साबित करते हैं कि अपीलकर्ता इस तथ्य के बारे में अपने साक्ष्य के बोझ का निर्वहन करने के लिए बाध्य होंगे कि ममता की मृत्यु कैसे हुई।

69. यह शायद ही इस बात को समझने की जरूरत है कि ममता की मृत्यु कैसे हुई, इस तथ्य के बारे में साक्ष्य के बोझ से पहले, अपीलकर्ताओं द्वारा इसके बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जैसा कि पहले ही टिप्पणी की गई थी, धारा 313 द०प्र०स० के तहत अपने बयानों में। अपीलकर्ताओं को उस आवश्यकता की कठोरता से मुक्त करना और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना, इससे एक न्यायसंगत निर्णय होगा, कम से कम, जो अपीलकर्ताओं के दायित्व के बारे में कहा जा सकता है, इस तथ्य के बारे में किसी प्रकार के सबूत पेश करना है कि ममता की मृत्यु कैसे हुई। अन्यथा, अ०सा०-1 की गवाही का दोषी हिस्सा अ०सा०-4 और मेडिको-लीगल साक्ष्य, जिसमें शव परीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श क-2, एफएसएल रिपोर्ट, जिसमें प्रदर्श क-12 शामिल है, और अ०सा०-5 की गवाही इसके पहले दिए गए कारणों से उचित संदेह से परे साबित होगी।

70. दूसरी ओर, यदि अपीलकर्ताओं ने ममता की मृत्यु के लिए अग्रणी परिस्थितियों के बारे में कुछ सबूत दिए थे, जो उनकी बेगुनाही के अनुरूप थे, तो यह न्यायालय अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में सबूतों के साथ अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूतों पर विचार करने के लिए बाध्य होगा, यदि वास्तव में अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित कर दिया है। ऐसा क्यों है, इस पर आगे विचार किया जाएगा।

71. जबकि एक आपराधिक अभियोजन में, उचित संदेह से परे पूरे मामले को स्थापित करने के अर्थ में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है, एक बार जब अभियोजन पक्ष उस मानक द्वारा मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करता है, तो अभियोजन पक्ष को दूर करने के लिए कुछ सबूत जोड़ने के लिए बचाव पक्ष पर साक्ष्य का बोझ बदल जाता है। यदि दोषमुक्त करने के लिए कुछ सबूतों का नेतृत्व करने के माध्यम से साक्ष्य का बोझ दूर

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं किया जाता है, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है, जहां इसके अखंडित दृष्टिकोण पर, अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे स्थापित होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 102 के तहत परिकल्पित दायित्व या सबूत का बोझ धारा 101 के तहत बहुत अलग बोझ है। जबकि धारा 101 कार्यवाही की प्रकृति के आधार पर, सबूत के किसी भी मानक द्वारा मामले को पूरी तरह से साबित करने के लिए पार्टी पर एक दायित्व के अर्थ में बोझ की बात करती है, साक्ष्य का बोझ या तो प्रारंभिक दायित्व है या दूसरे पक्ष के साक्ष्य द्वारा एक पक्ष पर साक्ष्य का नेतृत्व करने और इसे तराजू में रखने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो तब न्यायालय को सभी सबूतों पर विचार करने के लिए बाध्य करेगा यदि धारा 101 के तहत सबूत का बोझ उठाने वाले पक्ष ने इसे खारिज कर दिया है और अपना मामला स्थापित किया है या विफल रहा है। यदि, हालांकि, प्रारंभिक साक्ष्य बोझ या मुकदमे के दौरान स्थानांतरित किए गए एक को बिल्कुल भी मुक्त नहीं किया जाता है, तो न्यायालय के लिए बहुत अधिक निर्णय लेने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि साक्ष्य के बोझ में चूक करने वाला पक्ष कुछ सबूत पेश करने में असमर्थता के कारण विफल हो जाएगा।

72. यह तथ्यों को साबित करने के लिए बोझ का निर्वहन करने में विफलता का मामला नहीं है, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत परिकल्पित अपीलकर्ताओं के ज्ञान के भीतर। यह थोड़ा अंतर वाला मामला है। धारा 106 आकर्षित होगी यदि घटना को देखने के लिए अपीलकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के अलावा कोई अन्य गवाह नहीं होगा। यहां मृतक की बहन अ०सा०-2 में सच देखने और बोलने के लिए पारिवारिक बंधन से बेदाग एक आंख थी। हालांकि, वह एक समझौते के बाहरी विचारों से प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी उन तथ्यों की गवाही दी है जो पर्याप्त रूप से दोषी हैं और अन्य गवाहों के साक्ष्य के साथ-साथ मेडिको-लीगल साक्ष्य के साथ भी रखे गए हैं, उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष को साबित करते हैं, जब तक कि अपीलकर्ताओं ने अपने अपराध को असंभव बनाने के लिए सबूत नहीं दिए। अपीलकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया है; यहां तक कि उनके खिलाफ पेश होने वाले दोषसिद्धि तथ्यों और सबूतों के बारे में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया।

73. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह, (2025) 8 एस.सी.सी. 545 में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से पुष्ट किया गया है, जो कि एक ऐसा मामला है

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को आकर्षित किया गया था, व्यापक आधार पर सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया था, जिसमें वह भी शामिल है जो यहां लागू होता है। बलवीर सिंह (उपरोक्त) में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है:

"88. पूर्वगामी को दोहराने के लिए: विभिन्न नियमों के निचले भाग में क्या निहित है, जो किसी के मामले के सबूत में साक्ष्य पेश करने के साक्ष्य बोझ या बोझ को स्थानांतरित करता है, जो कि प्रेरक बोझ या सबूत के बोझ के विपरीत है, यानी अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को साबित करने के लिए और जो कभी नहीं बदलता है, यह विचार है कि अभियोजन पक्ष के लिए अपने हाथ से कुछ मुद्दों पर पूरी तरह से ठोस सबूत देना असंभव है और इसलिए यह अभियुक्त पर निर्भर करता है कि यदि वह भागना चाहता है तो वह उन पर सबूत दे। अभियोजन पक्ष द्वारा सकारात्मक तथ्यों को हमेशा साबित किया जाना चाहिए। लेकिन यही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता। यह अभियोजन पक्ष के लिए नहीं है कि वह सभी संभावित बचावों या परिस्थितियों का अनुमान लगाए और उन्हें समाप्त करे जो किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती हैं। फिर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है, तो अधिनियम के चरित्र और परिस्थितियों का सुझाव है, तो यह अभियोजन पक्ष के लिए अन्य सभी संभावित इरादों को खत्म करने के लिए नहीं है। यदि अभियुक्त का कोई अलग इरादा था जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में एक तथ्य है और जिसे उसे साबित करना होगा (देखें प्रोफेसर ग्लेनविले विलियम्स-अपराध का प्रमाण, अध्याय 7, पृष्ठ 127 और निम्नलिखित) और दिलचस्प चर्चा-प्रस्तर-527 नकारात्मक कथन और प्रस्तर-528 - पृष्ठ 438 पर "सकारात्मक प्रति-साक्ष्य की आवश्यकता है" और केनी की आपराधिक कानून की रूपरेखा की फोइल, 17वां संस्करण। 1958.

89. लेकिन धारा 106 का उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहां प्रश्न में तथ्य, इसकी प्रकृति के संबंध में, ऐसा है कि न केवल अभियुक्त को बल्कि दूसरों को भी जानने में सक्षम है, यदि वे उस समय उपस्थित थे। किसी भी व्यक्ति के कार्य या आचरण में अंतर्निहित इरादा शायद ही कभी एक ऐसा मामला होता है जिसे निर्णायक रूप से स्थापित किया जा सकता है; यह वास्तव में केवल उसी व्यक्ति को पता



चलता है जिसके मन में इरादा की कल्पना की जाती है। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि किसी कार्य के चरित्र और परिस्थिति से पता चलता है कि यह एक विशेष इरादे से किया गया था, तो इस धारा के उदाहरण (ए) के तहत, यह माना जा सकता है कि उसका वह इरादा था, जब तक कि वह तत्सम विपरीत साबित न हो।

90. सबूत के बोझ और सबूत के साथ आगे बढ़ने के बोझ के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। आम तौर पर, किसी मुद्दे की नींव के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक किसी भी सकारात्मक प्रस्ताव पर सबूत का बोझ नहीं बदलता है, लेकिन गवाही के अनुसार सबूत का बोझ या स्पष्टीकरण का बोझ एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो सकता है। इस प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य पेश किए हैं, जो यदि अदालत द्वारा विश्वास किया जाता है, तो उन्हें उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के बारे में आश्वस्त किया जाएगा, तो अभियुक्त, यदि एक स्थिति में है, तो उसे प्रतिसंतुलनकारी साक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यदि उसके पास ऐसे सबूत हैं। जब तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में होते हैं, तो ऐसे तथ्यों के साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उस पर होता है, चाहे प्रस्ताव सकारात्मक हो या नकारात्मक। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया हो, क्योंकि अदालत को अभी भी यह पता लगाना चाहिए कि वह दोषी ठहराने से पहले एक उचित संदेह से परे दोषी है। हालांकि, अभियुक्त की ओर से सबूत पेश करने में विफलता को अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा इंगित निष्कर्ष की पुष्टि करने या उससे उत्पन्न होने वाली अनुमानों की पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। हालांकि कानूनी रूप से अपनी ओर से सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभियुक्त को एक व्यावहारिक मामले के रूप में सबूत के साथ आगे बढ़ना आवश्यक लग सकता है। यह अभियोजन पक्ष पर टिके सबूत के बोझ को नहीं बदलता है [देखें: बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य [बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, (2023) 16 एस.सी.सी. 575] और अनीस बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) [अनीस बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी), (2024) 15



एस.सी.सी. 48: 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 757: 2024 आई.एन.एस.सी.
368J/ (महत्व सन्निविष्ट)

74. अब हम यह जांचने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या प्रस्तुत मामले में, हम चश्मदीद गवाह सहित सभी गवाहों की गवाही की अवहेलना करते हैं, जिन्होंने दोषमुक्ति बोलने का प्रयास किया था और अभियोजन पक्ष द्वारा कम से कम औपचारिक रूप से शत्रुतापूर्ण और जिरह घोषित की गई थी, क्या हम अभी भी मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक के रूप में मान सकते हैं और तदनुसार अभियोजन पक्ष के मामले के मूल्य का मूल्यांकन कर सकते हैं।

75. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय प्रकाश शर्मा, 2024 (12) एडीजे 256 (डीबी) (एलबी) में इस न्यायालय की पीठ के फैसले में, यह टिप्पणी की गई थी:

"28. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह खुद को याद दिलाना उचित होगा कि यह एक ऐसा मामला है जहां चश्मदीद गवाह, अर्थात् अंसा०-1-उदय स्वरूप भारद्वाज, जो मामले के सूचनाकर्ता हैं, उनके दोस्त अंसा०-2-राजीव दीक्षित और उनके चौकीदार अंसा०-3-भरत ने दो व्यक्तियों, कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके बेटे कपिल गुप्ता की हत्या के अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और वे सभी मुकर गए। अभियोजन पक्ष कुछ परिस्थितियों पर भरोसा करके अपीलकर्ताओं पर लगाए गए आरोप को घर लाने का प्रयास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चश्मदीद गवाहों की शत्रुता के बावजूद दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, बशर्ते कि इस तरह के परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए बार-बार किए गए फैसलों के एक कैटेना द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराए गए अच्छी तरह से स्थापित परीक्षण में खरे उतरें। इस संबंध में, हम परमजीत सिंह @ पम्मा बनाम परमजीत के मामले का उल्लेख कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 439, जिसमें सभी सात चश्मदीद गवाह मुकर गए हैं, शीर्ष अदालत द्वारा यह देखा गया कि मामले का फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि चूंकि सभी चश्मदीद गवाह मुकर गए हैं, इसलिए यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला बना हुआ है।



76. अब, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में कानून संदेह से परे तय हो गया है और मानक सटीक है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले को अभियोजन पक्ष द्वारा इस तरह से स्थापित करने की आवश्यकता है कि दोषी परिस्थितियों को किसी भी अन्य परिकल्पना को बाहर करने के लिए एक श्रृंखला पूरी करनी चाहिए, लेकिन एक आरोपी के लिए अपराध के अनुमान की ओर ले जाता है। इस संबंध में शरद बिरधीचंद सारदा बनाम शरद बिरधीचंद सारदा का संदर्भ दिया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस.सी.सी. 116.

77. हम पहले ही इस मामले में किसी न किसी रूप में सामने आने वाले सबूतों की जांच कर चुके हैं और इसके सभी विवरणों के लिए इसे बार-बार पढ़ना एक निरर्थक अभ्यास होगा।

78. चश्मदीद गवाह की गवाही को एक तरफ रखते हुए, जिसने घटना को देखा, बुद्धि के लिए, अंसा०-2, निम्नलिखित परिस्थितियां अभिलेखों पर साक्ष्य के आधार पर अच्छी तरह से स्थापित हैं: तथ्य यह है कि मृतक को अपने वैवाहिक घर में रहते हुए कुछ चोट लगी थी; तथ्य यह है कि चोट से संबंधित घटना गंभीर और खतरनाक थी कि उसकी छोटी बहन, अंसा०-2 ने अपने पिता, अंसा०-1 को फोन किया, उसे मृतक के ससुराल में आने के लिए कहा; तथ्य यह है कि जब मृतक के पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसके ससुराल पहुंचे, तो वह पूरी तरह से बीमार थी और स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में थी, कि अंसा०-1 और परिवार के अन्य सदस्यों ने सोचा कि उन्हें उसे बुलंदशहर जिले में उसके पैतृक गांव से अलीगढ़ के एक अस्पताल में ले जाना चाहिए; तथ्य यह है कि उसके स्वास्थ्य की अनिश्चित स्थिति के बावजूद, मृतक के ससुराल वाले उसे अस्पताल नहीं ले गए या चिकित्सा सहायता को कॉल नहीं किया; तथ्य यह है कि मृतक के ससुराल वाले, अपने पिता और परिवार को आते देखकर, अपना घर छोड़ दिया और चले गए; तथ्य यह है कि बुलंदशहर जिले में अपने ससुराल के गांव से अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, मृतक का अतरौली में निधन हो गया; तथ्य यह है कि मृतक के निधन के तुरंत बाद, पहले सूचनाकर्ता, अंसा०-1 ने पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें जीवित रहते हुए मृतक के शब्दों का उल्लेख किया गया था कि उसे उसके पति, सास, ससुर और भाभी द्वारा जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था; तथ्य यह है कि शव परीक्षण रिपोर्ट में, डॉक्टर ने मस्तिष्क को भीड़भाड़ में पाया, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय की थैली और प्लीहा सहित भीड़भाड़ में, लेकिन मृत्यु के कारण का पता लगाने में सक्षम नहीं होने के कारण, हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के लिए विसरा को संरक्षित किया; तथ्य यह है कि विधि

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में, विसरा की जांच पर यह पाया गया कि ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक जहर मौजूद था; तथ्य यह है कि मृतक की स्पष्ट रूप से उसके वैवाहिक घर में लगी कुछ चोट के परिणामस्वरूप एक अप्राकृतिक मृत्यु हो गई, जहां मृत्यु का कारण जहर है; तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने धारा 313 द०प्र०स० के तहत या किसी अन्य स्तर पर, जांच या उनकी जिरह सहित अपने बयानों में, परिस्थितियों के बारे में एक बोधगम्य स्पष्टीकरण के साथ नहीं आया है, जो मृतक की मृत्यु और उनकी बेगुनाही या गैर-भागीदारी दोनों के अनुरूप है; और, तथ्य यह है कि मृतक का अंतिम संस्कार उसके ससुराल के घर में किया गया था, न कि उसके ससुराल में, जो अनिवार्य रूप से मामला होता, अगर उसकी मृत्यु अपीलकर्ताओं के लिए प्राकृतिक और दोष से मुक्त होती।

79. इन सभी परिस्थितियों को एक साथ रखा गया है और उनके अस्तित्व के बारे में किसी भी प्रकार की दुर्बलता या संदेह में नहीं है। एक साथ विचार की जाने वाली परिस्थितियाँ एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ताओं के अपराध को छोड़कर, किसी भी अन्य संभावना को बाहर करती है। हालाँकि, जैसा कि पहले टिप्पणी की गई है, इन परिस्थितियों की स्थापना पर, अभियोजन पक्ष ने निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के तहत साक्ष्य पेश करने का बोझ डाल दिया, जो अभी भी इन परिस्थितियों के अनुरूप उनकी बेगुनाही का प्रदर्शन कर सकता है। यदि अपीलकर्ताओं ने अपनी बेगुनाही प्रदर्शित करने के लिए कुछ सबूत पेश किए थे, तो उनके खिलाफ दिखाई देने वाली इन परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा किया गया था, तो हमें अपने निष्कर्ष निकालने के लिए तस्वीर की समग्रता पर विचार करना होगा, यदि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने में सफल रहा है। चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा इन परिस्थितियों के बचाव में कोई सबूत या यहां तक कि कोई मामला सामने नहीं रखा गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष के बोझ को मुक्त किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला सभी उचित संदेह से परे साबित हुआ है। इसलिए, निष्कर्ष यह है कि गवाहों के साक्ष्य के आधार पर, उनकी शत्रुता के बावजूद, और उन सबूतों को नजरअंदाज करते हुए, केवल परिस्थितियों से, अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विचारण न्यायाधीश कमोबेश अपने स्वयं के कारणों से एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो हमारी तुलना में थोड़ा अलग हो सकता है। हालांकि, हमें यह टिप्पणी करनी चाहिए कि हम विचारण न्यायाधीश



से सहमत नहीं हैं कि यह एक ऐसा मामला है, जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को बिल्कुल भी लागू किया जा सकता है। इसलिए, हम उन निष्कर्षों से सहमत हैं जो विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ मोटे तौर पर उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उनके तर्क से भी सहमत हैं।

80. परिणाम में, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

81. आपराधिक अपील संख्या 5320 वर्ष 2021 में, नानकराम और मुन्नी जमानत पर हैं। वे चार सप्ताह के भीतर बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे ताकि उन्हें सुनाई गई सजा काट सकें। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाएंगे और जमानत से छुट्टी दे दी जाएगी।

82. इस आदेश को रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को सूचित किया जाए।

83. विचारण न्यायालय के अभिलेखों को तुरंत भेज दिया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर)

जनवरी 20, 2026